राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 24 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-32 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

देश की पहली आतंकवाद-विरोधी नीति जारी, केंद्र ने प्रहार नाम दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने सोमवार को 'PRAHAAR' नाम से भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति जारी की। इसमें हर तरह के आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए एक व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित ढांचा बताया गया है। आठ पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें पूरी सरकार और पूरे समाज की भागीदारी वाला तरीका अपनाने की बात कही गई है, जो मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित होगा। साथ ही कट्टरपंथउन जैसे हालात को खत्म करने पर भी ध्यान होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। नीति में भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई गई है। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धार्मिक, जातीय या वैचारिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत हर तरह के आतंकवाद की हमेशा कड़ी निंदा करता रहा है। नीति कहती है कि इसका मुख्य मकसद भारतीय नागरिकों और देश के हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों को रोकना है। इसके अलावा खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित जवाब देना है। नीति में कहा गया है कि आतंक के खिलाफ सरकार के अलग-अलग विभागों की ताकत को मिलाकर काम करना है।

दिल्ली विधानसभा-सचिवालय को बम ब्लास्ट की धमकी

■ आर्मी-एयरफोर्स स्कूल को थ्रेट मिली

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा भवन, दिल्ली सचिवालय और लाल किले को बम ब्लास्ट में उड़ाने की धमकी दी गई है। सोमवार को खालिस्तानी ग्रुप का धमकी वाला ईमेल भेजा गया। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं, विधानसभा भवन की सर्चिंग की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वॉड सर्च में जुटीं लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं, लाल किला की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले दिल्ली स्थित धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी। जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वॉड और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें स्कूल पहुंची थी। पूरा कैंपस खाली कराया गया। जांच में कुछ भी नहीं मिला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल में दिल्ली बनेगा खालिस्तान की धमकी दी गई थी। लिखा था कि अगले 3 दिनों के भीतर आर्मी स्कूल, लाल किला और मेट्रो स्टेशनों पर विस्फोट हो सकते हैं।

लखनऊ में डबल डेकर बस पलटी, 6 की मौत

21 यात्री घायल, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा

लखनऊ (एजेंसी)। डबल डेकर बस पलट गई। इसमें 6 की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए। 3 की मौके ही मौत हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 8 घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर बस छोड़कर भाग गए। बस लुधियाना (पंजाब) से दरभंगा (बिहार) जा रही थी। बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से जा रही बस पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गोसाईगंज के पास पलटी। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से बस को उठाकर टोल प्लाजा ले जाया गया। कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल के सभी डॉक्टरों को बुला लिया गया है। वहीं, अफ्छड प्रवर्तन आलोक यादव भी मौके पर पहुंच गए हैं। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। हादसा बेहद दर्दनाक है। हादसे के बाद मौके से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें कई यात्रियों के हाथ-पैर शरीर से अलग दिख रहे

हैं। दुर्घटना की जगह पर चारों ओर खून ही खून नजर आ रहा है। हादसे में घायल यात्री सड़क किनारे तड़प रहे हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घटना के बाद सड़क पर फैले खून को प्रशासन ने तत्काल सफाईकर्मियों से धुलवा दिया। मौके की साफ-सफाई कराकर यातायात सामान्य कराया गया है। इस दौरान काफी देर तक जाम लग गया।\ एआरटीओ आलोक कुमार यादव ने बताया- डबल डेकर बस पलटी है। ड्राइवर और क्लीनर यहां से चले गए हैं। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों को ट्रॉमा सेंटर भी भेजा गया है। प्रथमदृष्टया ड्राइवर की झपकी से हादसा होना लग रहा है। शराब की बोतलें मिलने के सवाल पर कहा कि पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। जांच में सब कुछ साफ होगा। एक प्रत्यक्षदर्शी अंश पटेल ने बताया- हमारा पास में ही घर है। हम एक्सप्रेस-वे के नीचे से जा रहे थे। अचानक देखा कि बस सांप की तरह लहराते हुए जा रही है। उसके बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। यह डबल डेकर बस हरियाणा नंबर की है। इसे साल-2019 में रजिस्टर्ड कराया गया था इस गाड़ी का फिटनेस 27 अगस्त, 2027 तक है। गाड़ी का इंश्योरेंस भी 27 अगस्त तक है। पॉल्यूशन 11 फरवरी 2027 तक और 2019 जून तक के लिए परमिट है। बस लुधियाना से दरभंगा जा रही थी। उसमें 40 से ज्यादा लोग सवार थे। ज्यादातर यात्री मजदूर थे। सभी होली पर घर जा रहे थे। कई यात्रियों को मामूली चोट आई है।

पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पीएम ने लिखी चिट्ठी

सीएए का जिक्र, घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास के साथ कानून-व्यवस्था पर बात रखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला भाषा में एक खुला पत्र लिखा है। इमसें उन्होंने उअअ का जिक्र करते हुए घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने पत्र की शुरूआत जय मां काली के जयकारे के साथ की। उन्होंने लिखा- अब बस कुछ ही महीने में पश्चिम बंगाल का भाग्य सुनिश्चित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह आपके सोचे-समझे फैसले पर निर्भर करता है। उन्होंने लिखा कि मेरे सोनार बंगाल के सपने देखने वाला हर एक जवान, बूढ़ा और महिलाएं आज बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा से आज मेरा हृदय भी व्यथित है। इसलिए मैंने मन की गहराइयों से एक संकल्प लिया है, पश्चिम बंगाल को विकसित और

पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना

स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास में अग्रणी था, लेकिन अब स्थिति चिंताजनक है। रोजगार के अभाव में युवा पलायन कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

समृद्ध बनाने का संकल्प। उन्होंने आगे लिखा- पिछले 11 वर्षों में देशवासियों के आशीर्वाद को ताकत बनाकर मेरी सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण से लेकर युवाओं के सपनों को साकार करने तक, और मातृशक्ति के सशक्तिकरण से लेकर समाज के हर वर्ग तक, हमारी नीतियों और निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आज साफ दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार के असहयोग और विरोध के बावजूद, आज पश्चिम बंगाल के करीब 5 करोड़ लोग ह्यजन-धन योजनाह्न के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। ह्यस्वच्छ भारत अभियानह्न के तहत राज्य में 85 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। जब राज्य की सत्ताधारी पार्टी गरीबों का निवाला छीन रही है, तब हमने छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को 2.82 लाख करोड़ रुपये का लोन देकर मदद का हाथ बढ़ाया है। अटल पेंशन योजना के तहत 56 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को रसोई गैस देकर माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर मैं धन्य हूं। जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, आज पश्चिम बंगाल में वही अन्नदाता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में ह्यकिसान सम्मान निधिह्न के जरिए 52 लाख से अधिक किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता था और औद्योगिक विकास में अग्रणी था। लेकिन आज इस गौरवशाली राज्य की जर्जर हालत देखकर मेरा मन व्यथित हो उठता है। पिछले छह दशकों के कुशासन और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल को जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसे बयान नहीं किया जा सकता।

भारत मंडपम प्रदर्शन मामले में पुलिस की कार्रवाई

■ दो और प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई प्रदर्शन से जुड़े प्रकरण में की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय अजय कुमार विमल और 24 वर्षीय राजा गुर्जर के रूप में हुई है। बता दें इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा इससे पहले चार प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के चार कार्यकताओं को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पहले गिरफ्तार किए गए कार्यकताओं में बिहार से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण हरि, बिहार के आईवाईसी प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश के आईवाईसी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना के नरसिम्हा यादव शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर देश विरोधी नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक, विरोध के दौरान रोकने की कोशिश में तीन लोग घायल भी हुए। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के पीछे किसी साजिश की जांच, फंडिंग के स्रोत और टी-शर्ट कहां छपी थीं, इसका पता लगाना जरूरी है। पुलिस ने इनके खिलाफ लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य निभाने से रोकने, लोक सेवक पर हमला करने, घृणास्पद भाषण देने, आपराधिक साजिश आदि के आरोप में मामला दर्ज किया है।

एचएएल का दावा: तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ: मामूली खराबी थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सोमवार को इंडियन एयर फोर्स (IAF) के फाइटर जेट तेजस के क्रैश की खबरों को गलत बताया है। HAL ने कहा है कि ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। HAL ने बताया कि वह एयरफोर्स के साथ मिलकर तकनीकी गड़बड़ी की जांच कर रही है और उसे जल्द ठीक करेगी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट्स में सबसे बेहतर में से एक है। सूत्रों

के हवाले से दावा किया था कि 7 फरवरी को लैंडिंग के दौरान तेजस का ब्रेक फेल हो गया था। इसके कारण एयरक्राफ्ट रनवे से आगे निकल गया। हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। तेजस ट्रेनिंग उड़ान के बाद एयरबेस पर लौट रहा था। सूत्रों ने दावा किया कि घटना के बाद एयरफोर्स नेतेजस जेट के पूरे बेड़े को टेक्निकल जांच के लिए ग्राउंड कर दिया। यानी जांच पूरी होने तक विमान उड़ान नहीं भरेंगे। हादसे पर IAF की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। दावे के मुताबिक, तेजस जेट से जुड़ा यह तीसरा हादसा है। पहला हादसा मार्च 2024 में हुआ था, जब जैसलमेर के पास एक तेजस जेट क्रैश हो गया था।

नेपाल- बस हाईवे से नदी में गिरी, 18 की मौत: 25 घायल

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि, यह किस देश से थे और इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) के मुताबिक, अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस (Ga 1 Kha 1421) पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा देर रात करीब रात 1:30 बजे धादिंग जिले के बेनिघाट रोरांग इलाके में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की अन्य वजहों की भी जांच कर रही है।

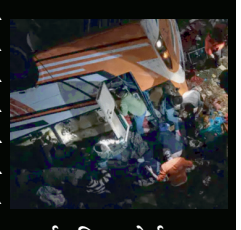

तारिक रहमान के पीएम बनते ही बांग्लादेशी सेना में फेरबदल

भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गईं। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हाफिजुर रहमान को मेजर जनरल पद पर प्रमोट किया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फैंट्री डिविजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ (CGS) बनाया गया है। वे इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह ली है, जिन्हें रिटायरमेंट लीव पर भेज दिया गया था। मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस (DGFI) का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे आर्मी मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम की जगह ली है, जिन्हें फिलहाल विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को सशस्त्र बल डिविजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर (PSO) बनाया गया है। वे इससे पहले चटगांव स्थित 24वीं इन्फैंट्री डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) थे। मौजूदा PSO लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कामरुल हसन को विदेश मंत्रालय में राजदूत के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मेजर जनरल जेएम एमदादुल इस्लाम को ईस्ट बंगाल रेजिमेंटल सेंटर का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। वहीं मेजर जनरल फिरदोस हसन सलीम को 24वीं इन्फैंट्री डिविजन का GOC बनाया गया है। सरकार मजबूत होगी- सेना के बड़े पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति से नई सरकार को सेना का साफ समर्थन मिलेगा। इससे सरकार के खिलाफ बगावत या अस्थिरता की संभावना कम हो सकती है, खासकर जब हाल में देश में राजनीतिक तनाव रहा है।

बांग्लादेश सेना में फेरबदल क्यों हुआ?

ये बड़ा फेरबदल तारिक रहमान की नई BNP सरकार के लिए सेना पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। फरवरी 2024 में छात्र आंदोलन से शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने सेना के कई शीर्ष पदों पर अपने करीबी या पुरानी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को तैनात किया था। अब 12 फरवरी 2026 के चुनाव में इठढ की भारी जीत के बाद तारिक रहमान 17 फरवरी को प्रधानमंत्री बने, तो नई सरकार ने जल्दी से इन पदों पर बदलाव किए। इसके पीछे मुख्य वजह यह माना जा रहा है कि पुराने अधिकारियों (जो यूनुस सरकार या हसीना काल से जुड़े थे) को हटाकर इठढ के करीबी या नई सरकार के प्रति वफादार अधिकारियों को महत्वपूर्ण कमांड और खुफिया पद दे रही है, ताकि सेना नई सरकार के खिलाफ कोई असंतुलन पैदा न करे और सेना मजबूत हो सके।

दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे कोयला आधारित उद्योग?

300 किमी. दायरे वाले प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं और अलग-अलग मुद्दों पर जवाब तलब किया है। अदालत ने खास तौर पर कोयला आधारित उद्योगों, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान उड़ने वाली धूल और वाहनों के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में लगातार वायु गुणवत्ता की दिक्कत से निपटने के लिए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची

विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि वह कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के सुझावों के आधार पर 12 मार्च को गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे की जांच करेगी। इसने भवन निर्माण और तोड़-फोड़ की वजह से होने वाली धूल से निपटने के लिए सीएक्यूएम के सुझाए गए तरीकों पर सभी स्टेकहोल्डर्स से भी जवाब मांगा।पीठ ने इस सुझाव पर भी केंद्र से जवाब मांगा कि दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में कोई नया कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित न किया जाए।

गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण पर 12 मार्च को सुनवाई

इसने केंद्र सरकार के मंत्रालयों को एनसीआर के अंदर कोयला-आधारित इंडस्ट्रीज को धीरे-धीरे खत्म करने के मकसद से एक संयुक्त प्रस्ताव जमा करने को कहा गया है। बेंच ने आदेश दिया, प्रस्ताव में सबसे पहले इंडस्ट्रीज की पहचान की जाएगी और यह तय किया जाएगा कि उनके लिए कौन से वैकल्पिक ईंधन स्रोत दिए जा सकते हैं। बेंच ने दिल्ली सरकार को सीएक्यूएम द्वारा सुझाए गए इन लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन को लागू करने के लिए एक खास एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा, कमीशन ने उन संबंधित एजेंसियों की पहचान की है जिनसे एक्शन लेने की उम्मीद है। इसलिए हम दिल्ली सरकार को इन उपायों को लागू करने के लिए एक प्रपोज्ड एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश देते हैं। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के चलने से प्रदूषण बढ़ने का सवाल भी उठा। बेंच ने कहा कि इसका परीक्षण किए जाने की जरूरत है। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एआई तकनीक में विश्व का नेतृत्व करेगा भारत

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

राजधानी नई दिल्ली के में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का शनिवार को समापन हो गया, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता ने भारत को ग्लोबल साउथ में अग्रणी नेतृत्वकारी देश के रूप में स्थापित कर दिया है। इस शिखर सम्मेलन में 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया जाना न केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि है, बल्कि यह भारत की उस सोच की वैश्विक स्वीकृति भी है, जो तकनीक को मानव कल्याण से जोड़कर देखती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण औउखर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को जिस व्यापक वैश्विक समर्थन मिला है, वह बताता है कि दुनिया तकनीकी प्रगति को केवल आर्थिक लाभ लाभ के नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के संदर्भ में भी देखना चाहती है।21 फ़रवरी को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट डिक्लेरेशन का समर्थन किया। इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन में किए गए सारे कमिटमेंट स्वैच्छिक हैं, यानी ये उन देशों की इच्छा पर निर्भर है कि वे इसके मुताबिक़ कितना काम करते हैं।

इस डिक्लेरेशन में देशों ने इस समिट में सात चक्र में हुई चर्चाओं का संज्ञान लिया और कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में हुए एआई समिट से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के विकास में अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान भी किया जाएगा।

आपको पता हो कि 88 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह सिद्धांत केवल एक सांस्कृतिक वाक्यांश नहीं, बल्कि तकनीकी विकास के लिए एक नैतिक दिशा है। ऐसे समय में जब एआई को लेकर विश्व में प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण और प्रभुत्व की राजनीति हावी है, भारत ने समावेशी और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर एक संतुलित विकल्प दिया है। समिट के दौरान एआई क्षेत्र में 250 अरब डॉलर के संभावित निवेश का भरोसा जताया जाना भारत की आर्थिक क्षमता और नीति स्थिरता पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं, बल्कि नवाचार, रोजगार और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का अवसर है। साथ ही यह फंडिंग दर्शाती है कि दुनिया भारत को एआई के भविष्य के केंद्र के रूप में देख रही है। भारत पहले से ही आईटी और डिजिटल सेवाओं में वैश्विक केंद्र रहा है। अब एआई में नेतृत्व का अर्थ है कि उच्च कौशल वाले रोजगार, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा और वैश्विक कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र बनना। यदि यह निवेश सही दिशा में लागू हुआ, तो भारत न केवल उपभोक्ता बल्कि एआई समाधानों का प्रमुख उत्पादक भी बन सकता है। एआई की तीन प्रगति ने कई नैतिक और सुरक्षा संबंधी प्रश्न भी खड़े किए हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदमिक पक्षपात, साइबर सुरक्षा और रोजगार पर प्रभाव जैसी चिंताएं गंभीर हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट का एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजना था। भारत ने जिस प्रकार विकासशील देशों की आवाज को मंच दिया, वह अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह तथ्य कि पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ, अपने आप में ऐतिहासिक है। लंबे समय तक तकनीकी विमर्श विकसित देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। भारत ने इस परंपरा को बदलते हुए यह दर्शाया कि नवाचार और नीति-निर्माण में विकासशील देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ग्लोबल साउथ के कई देश डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और डेटा आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर आदि पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है। अब एआई के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का साझा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिससे छोटे और मध्यम आय वाले देशों को लाभ हो। भारत की युवा आबादी और तकनीकी प्रतिभा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व की अग्रणी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के विशेषज्ञों की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश में गणित और इंजीनियरिंग की ठोस परंपरा है। चुनौती यह है कि यह प्रतिभा देश के भीतर शोध और उत्पाद विकास में रूपांतरित हो। जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में बढ़ती फंडिंग एक सकारात्मक संकेत है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा बताता है कि भारतीय उद्यमी केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि उत्पाद-निर्माता बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचने के लिए दीर्घकालिक और धैर्यपूर्ण निवेश आवश्यक होगा। अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, उद्योग और सरकार के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है। एआई अब प्रयोगशाला की अवधारणा नहीं, बल्कि व्यावसायिक वास्तविकता बन चुका है। वित्त, बीमा, दूरसंचार, ई-कॉमर्स और विनिर्माण क्षेत्रों में एआई आधारित विश्लेषण और स्वचालन से उत्पादकता में वृद्धि देखी जा रही है। यदि यह प्रवृत्ति स्थायी बनती है, तो एआई भारत की आर्थिक वृद्धि दर में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में एआई के प्रयोग से सामाजिक प्रभाव की व्यापक संभावनाए हैं। कृषि में सटीक खेती, स्वास्थ्य में रोग-पूर्वानुमान, शिक्षा में अनुकूलित शिक्षण और पर्यावरण में जलवायु विश्लेषण ये सभी क्षेत्र भारत के विकास एजेंडा से सीधे जुड़े हैं। यदि एआई समाधान ग्रामीण भारत तक पहुंचते हैं, तो समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति संभव है। भारत की बहुभाषी सांस्कृतिक संरचना एआई के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भारत भारतीय भाषाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट और बहुभाषी मॉडल विकसित करता है, तो वह न केवल घरेलू बाजार को सशक्त करेगा, बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए समाधान भी निर्यात कर सकेगा। मीडिया और रचनात्मक उद्योगों में एआई आधारित सामग्री निर्माण, अनुवाद और वॉयस इंटरफेस से नए आर्थिक अवसर उत्पन हो सकते हैं। एआई अवसंरचना के विस्तार के साथ ऊर्जा और जल-उपयोग जैसे प्रश्न भी जुड़े हैं। डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या पर्यावरणीय दबाव उत्पन कर सकती है। अतः एआई विकास को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता नीतियों के साथ संतुलित करना आवश्यक संतुलित कर है। तकनीकी नेतृत्व तभी टिकाऊ होगा जब वह पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। साथ ही, एआई के कारण पारंपरिक नौकरियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कौशल उन्नयन को नई पीढ़ी को उभरती तकनीकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत केवल डिजिटल उपभोक्ता रष्ट नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी विमर्श का नेतृत्व करने में सक्षम है। समिट में शामिल देशों के द्वारा निवेश का भरोसा भारत के लिए अवसर के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी लेकर आया है। एआई का युग मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी चरणों में से एक हो सकता है। यह तकनीक अवसर भी है और चुनौती भी। नई दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन ने यह संकेत दिया है कि भारत इस परिवर्तन को दिशा देने के लिए तैयार है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का सिद्धांत यदि केवल नारा न रहकर नीति और व्यवहार का हिस्सा बनता है, तो एआई का भविष्य अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी हो सकता है। अब अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि भारत और उसके साझेदार इस ऐतिहासिक सहमति को ठोस कदमों में कैसे बदलते हैं। यदि यह प्रयास सफल होता है, तो 2026 का यह सम्मेलन वैश्विक तकनीकी शासन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा।

आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 'नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए।इस समझौते को भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। पिछले साल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने यूरोप के नियमों का हवाला देते हुए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली में भारत सभी देशों को एक मंच पर लाने में सफल रहा। भारत का लक्ष्य एआई का लोकतंत्रीकरण करना है, ताकि यह तकनीक कुछ बड़ी कंपनियों या सीमित लोगों तक ही सीमित न रहे।यह घोषणा पत्र एआई के भविष्य के लिए एक दिशा तय करता है और साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है।इस के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को स्वीकार करना ही होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ग्लोबल साउथ के कई देश डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और डेटा आधारित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर आदि पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा चुका है। अब एआई के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का साझा मॉडल विकसित किया जा सकता है, जिससे छोटे और मध्यम आय वाले देशों को लाभ हो। भारत की युवा आबादी और तकनीकी प्रतिभा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है।

संपादकीय

कचरे का बोझ

सुप्रीम कोर्ट की इस गंभीर चिंता से सहमत हुआ जा सकता है कि ठोस कचरे का निस्तारण एक पर्यावरणीय मुद्दा मात्र नहीं है बल्कि यह जन-स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिये भी गंभीर चुनौती है। निस्संदेह, जब हम विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य हासिल करने की बात करते हैं तो नागरिक जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन भी एक अनिवार्य शर्त है। निस्संदेह, देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी नागरिक चुनौती बनी हुई है। देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र, कचरे के पहाड़ों से दबे लैंडफिल, अनुचित अपशिष्ट के अलग-अलग न होने तथा कचरे के प्रभावी निपटान की चुनौती से जूझ रहे हैं। ठोस कचरा निस्तारण से जुड़े नये नियम लागू होने से कुछ सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने देश में दशकों पुराने ठोस अपशिष्ट उपचार नियमों के अनुपालन में कोताही को लेकर चिंता व्यक्त की है। अदालत का मानना है कि बढ़ते कचरे का बोझ नागरिक जीवन की सुगमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा स्मार्ट सिटीज जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया है। यही वजह है कि न्यायालय ने समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए नियमों को सख्ती से लागू करने तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। सही मायनों में यह समय की भी जरूरत है। दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने स्थानीय निकायों और निर्वाचित प्रतिनिधियों मसलन पार्षदों व कॉर्पोरेटरों को दायित्व दिया है कि वे क्षेत्र के नागरिकों में स्वच्छता व ठोस कचरे के निस्तारण हेतु जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की पहल करें। जनजागरण से ही विकट होती समस्या के निस्तारण में मदद मिल सकती है। इस दिशा में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक चरण में दायित्व निर्वहन में विफल रहने पर जुर्माना विकल्प हो सकता है। वहीं बार-बार नियमों का उल्लंघन करने कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य है। निस्संदेह, ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता स्वच्छता और ठोस कचरे के निस्तारण में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करना कर्तव्य की अनदेखी करने पर कड़ा संदेश दे सकती है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों तथा नागरिक कल्याण संगठनों के बीच बेहतर तालमेल भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभा सकता है। आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास के साथ होने वाली उपभोग की वृद्धि और परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से शहरी अवसंरचना में सुधार के लिये की गई पहल, सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, यह एक हकीकत है कि नीति-निर्माताओं द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दिए बिना भारत के शहर बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिये संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे में ठोस कचरे से मुक्त भारत लक्ष्य महज एक सपना मात्र बनकर रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में सार्थक-सुनियोजित प्रयास दीर्घकाल में सार्थक साबित हो सकता है।

भारत की खुशहाली और आर्थिक मजबूती का आधारः केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

(24 फरवरी- केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस)

भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे उन हजारों हाथों का योगदान है, जो देश के राजस्व को मजबूत करने के लिए दिन-रात काम करते हैं। इन्हीं प्रयासों को सम्मान देने और आम जनता को कर व्यवस्था के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 फरवरी को देश में एक विशेष अवसर के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यह समय हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन साल 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनाया गया था। भले ही आज के दौर में टैक्स की प्रणालियां बदल गई हों और जीएसटी ने एक बड़ा स्थान ले लिया हो, लेकिन देश की तरक्की में उत्पाद शुल्क का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। एक आम नागरिक के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर टैक्स चुकाने से उसे क्या मिलता है। इसका जवाब बहुत ही सरल और सुंदर है। जब देश की फैक्ट्रियों में सामान बनता है और उस पर सरकार को शुल्क मिलता है, तो वही पैसा घूमकर समाज के कल्याण के लिए वापस आता है। हमारे गाँव और शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, अंधेरे को दूर करती बिजली की रोशनी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के आधुनिक हथियार, यह सब उसी कर के पैसे से संभव हो पाता है जो एक जिम्मेदार उद्यमी और नागरिक द्वारा चुकाया जाता है। इस प्रकार, कर का भुगतान करना केवल एक कानूनी काम नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्र की सेवा करने जैसा है।

इसी संदर्भ में यह समझना भी जरूरी है कि एक मजबूत कर प्रणाली ही देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी खतरों से निपटने की शक्ति प्रदान करती है। जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, तभी नई तकनीकों और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर निवेश किया जा सकता है। यह राजस्व ही है जो आपदाओं के समय राहत कार्य चलाने और देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक मुफ्त राशन और जरूरी सुविधाएं पहुँचाने में मदद करता है। बिना मजबूत वित्तीय आधार के कोई भी देश अपने नागरिकों के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए, उत्पाद शुल्क केवल एक सरकारी उगाही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम भी है, जो उद्योगों से कर लेकर समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान में खर्च किया जाता है। समय के साथ सरकारी कामकाज के तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। आज का दौर डिजिटल क्रांति का है और अब टैक्स चुकाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं रह गई है। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि कोई भी व्यापारी घर बैठे अपना हिसाब-किताब पूरा कर सकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि व्यापार करने में भी आसानी हुई है। यह समय उन अधिकारियों और कर्मचारियों के परिश्रम को भी सलाम करने का है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का खजाना सुरक्षित रहे और कहीं भी राजस्व की चोरी न हो। इसके साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि कर के माध्यम से एकत्र किया गया धन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ईंधन की तरह काम करता है।

जब हमारे उद्योग जगत में पारदर्शिता बढ़ती है, तो विदेशी निवेश भी भारत की ओर आकर्षित होता है। यह निवेश न केवल नई फैक्ट्रियां लगाता है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। हमारी आर्थिक नीतियां तभी सफल हो सकती हैं जब राजस्व विभाग और करदाता के बीच विश्वास का एक मजबूत रिश्ता हो। यही विश्वास आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर और भी ऊंचा स्थान दिलाएगा।

किसी भी महान राष्ट्र का निर्माण केवल सरकारी नीतियों से नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की ईमानदारी से होता है। जब हम ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, तो हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हैं। यह अवसर हमें यही सीख देता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। कर की चोरी न केवल अपराध है, बल्कि यह देश के विकास की गति को रोकने जैसा है। एक पारदर्शी और मजबूत कर व्यवस्था ही एक स्वस्थ समाज और शक्तिशाली भारत की पहचान है। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं की भूमिका और भी बढ़ जाती है। विकसित भारत का सपना तभी सच होगा जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझेगा। आइए, आज हम यह संकल्प लें कि हम कर चोरी जैसी बुराइयों को खत्म करने में सहयोग करेंगे और एक ईमानदार करदाता बनकर देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे। हमारी छोटी सी ईमानदारी ही कल के समृद्ध भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगीद्य

(लेखक पत्रकार हैं)

चिंतन मनन

दुःखी होने की बजाय दुःख का उपचार करें

लोगों से अपने सुना होगा कि संसार में दुःख ही दुःख है। असफलता मिलने पर कई बार आप भी यही सोचते होंगे, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। संसार में दुःख इसलिए है क्योंकि संसार में सुख है। अगर सुख नहीं होता तो दुःख का अस्तित्व भी नहीं होता है। ईश्वर हमें दुःख की अनुभूति इसलिए करवाता है ताकि हम सुख का एहसास कर पाएं, सुख के महत्व को समझें। श्रीमद्भागवद् में कहा गया है कि हमारा हर कर्म सुख पाने के लिए होता है। इसके बावजूद भी जीवन में कई बार हमें दुःख और कष्ट की अनुभूति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख और दुःख धूप-छांव एवं दिन और रात की तरह हैं। हम चाहें न चाहें दुःख को आना है। भगवान राम, श्री कृष्ण, बुध और महावीर को भी दुःख उठाना पड़ा। लेकिन इन महापुरूषों ने दुःख को गले लगाकर नहीं रखा बल्कि दुःख का उपचार किया।

दुःख रात के समान है। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य जिस तरह निरंतर प्रयास करता रहता है और नियत समय पर रात के अंधकार को पराजित करके दिन का प्रकाश ले आता है, इसी तरह हमें भी दुःख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दुःख से दुःखी होकर बैठने से दुःख और बढ़ता है लेकिन जब हम समाधान के लिए प्रयास करने लगते हैं तो दुःख का अंधेरा छंटने लगता है।

दुःख से हम जितना डरते हैं दुःख हमें उतना ही डराता है। अगर कोई यह सोचता है कि मृत्यु के बाद दुःख का अंत हो जाता है तो गरूड़ पुराण उसे जरूर पढ़ना चाहिए। गरूड़ पुराण में मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले कष्टों का वर्णन किया गया है। मृत्यु के बाद जीव को और भी कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि वहां तो शरीर भी नहीं होता है जिससे अपने दुःख का उपचार किया जा सकता है। सीता का हरण करके रावण ने राम को दुःख दिया। राम जी ने धैर्य से काम लिया और रावण जो उनके कष्ट का कारण था उसका पता लगाकर उसका अंत किया। पाण्डवों का सारा राज्य कौरवों ने छल से छीन लिया। पाण्डव अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते और दुःख का उपचार नहीं करते तो इतिहास में उनकी वीरता और साहस का बखान नहीं मिलता। इसलिए दुःख से दुःखी होने की बजाय दुःख का उपचार करना चाहिए।

विचार मंथन

न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर उठते सवाल?

(लेखक- सनत जैन)

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की खंडपीठ में सोमवार को एक असहज स्थिति देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, अडानी और अंबानी के लिए तुरंत बेंच बना दी जाती है। लेकिन एनजेएसी की महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका इतना कहते ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन्हें जमकर कोर्ट के अंदर फटकार लगाई। उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जो भी मेरी कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उसे लेकर भविष्य में सावधान रहें। आपने मुझे चंडीगढ़ और दिल्ली में देखा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, वैसा आगे भी करते रहेंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति शुक्रवार को भी बनी, जब एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुस्से में आ गए थे। उन्होंने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले वह वकीलों की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीकी की मदद से जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही हैं। उस पर उन्होंने नाराजी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका देखकर उन्होंने कहा ऐसा लगता है, भगवान जनहित याचिका के कानून से बचाए। कुछ इसी तरह की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में तब देखने को मिली जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा सरमा की हेट स्पीच की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। मुख्य न्यायाधीश ने उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को असम हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठतम वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई करने या असम के अलावा अन्य किसी हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश ने असहमति व्यक्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। जबकि कई राज्यों की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिछले कुछ महीनो में उसमें आदेश जारी किए हैं। जिन राज्यों की याचिका स्वीकार की गई हैं, उनमें अमूमन डबल इंजन की सरकारें हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर बार-बार सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जिस तरह से वरिष्ठ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली और सरकारी दबाव पर मामले की सुनवाई को लेकर असहमति बढ़ती चली जा रही है, इससे न्याय पालिका की एक ऐसी छवि विकसित हो रही है। सरकार या सरकार से जुड़े हुए मामलों में सुप्रीम कोर्ट त्वरित सुनवाई करने से बचती है। यदि याचिका स्वीकार हो भी जाती है। नोटिस जारी हो जाते हैं। उसके बाद तारीख पर तारीख का जो नया खेल शुरू होता है, उससे निश्चित रूप से सरकार को मदद होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित याचिका, एसआईआर का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। बिहार चुनाव के कई माह पहले से याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जिसका फैसला अभी तक नहीं आया है। इसी बीच बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए। सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख मिल रही है, सुनवाई भी हो रही है, कोई फैसला अभी तक नहीं आया। अगले कुछ ही महीना में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव होने हैं। जिसके कारण न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को चुनाव आयोग या सरकार को फायदा पहुंचाने के रूप में देखा जाने लगा है। करोडों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जो निर्देश चुनाव आयोग को दिए गए, उनका पालन चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती दे दी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मनमानी पर कोई रोक नहीं लगाई।

पिछले कुछ वर्षों में कई जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित हैं। उन पर अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। उसके कारण न्याय पालिका की छवि को लेकर आम आदमी में वह विश्वास नहीं रहा, जो न्यायपालिका के प्रति होना चाहिए। न्याय पालिका सरकार के खिलाफ कोई भी आदेश और निर्देश देने से बचती है। ऐसे मामलों से बचने के लिए या तो याचिका स्वीकार नहीं की जा रही हैं, यदि स्वीकार कर ली जाती है, तो उसकी समय पर सुनवाई और फैसला नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान जिस तरह की टिप्पणी करती हैं। इसका फायदा सरकार या सत्तारूढ़ दल को मिलता हुआ नजर आता है। जब उस मामले का आदेश आता है, सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की गई थीं, फैसले में कहीं उनका उल्लेख नहीं होता है। इससे भी न्याय पालिका के प्रति अविश्वास देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। दिल्ली में भयानक वायु प्रदूषण था। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की मुख्य खंडपीठ दिल्ली में है। केंद्र एवं राज्य में भाजपा की सरकार है। वांगचुक कई महीने से जेल में बंद है। हेवियस कॉरपस में पिछले कई महीनो से सुनवाई चल रही है। और भी कई अन्य मामले हैं, जिसमें तुरंत सुनवाई होकर निर्णय होने थे। ऐसे में न्यायपालिका की एक नई छवि बन रही है। न्यायपालिका सरकार के दबाव में है? वह सरकार के खिलाफ किसी मामले में फैसला करने से बचती है? विवादास्पद मामलों में आधे अधूरे फैसले देकर न्यायपालिका के जज अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आम लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बन गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आरबीआई बैठक में सीतारमण ने बैंकों को मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देने का सुझाव दिया

अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के प्रभाव पर तुरंत टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी

नई दिल्ली । नई दिल्ली में स्थित आरबीआई भवन में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 61वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मौजूद थे। सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ में बदलाव के प्रभाव पर तुरंत टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि वाणिज्य मंत्री हालात की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकों को अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए और बीमा उत्पादों की गलत बिक्री से बचना चाहिए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सोने-चांदी का आयात चिंताजनक स्तर पर नहीं है और रिजर्व बैंक इस पर नजर रख रहा है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण वैश्विक केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी है। आरबीआई गवर्नर ने आश्वासन दिया कि सोने के आयात को लेकर कोई खास चिंता नहीं है। बाहरी क्षेत्र मजबूत है और चालू खाता घाटा नियंत्रण योग्य स्तर पर है, जिससे अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने धोखाधड़ी के आरोपों से किया इनकार

हरियाणा सरकार ने सरकारी कामकाज से अस्थायी रूप से समिति से किया बाहर

नई दिल्ली । हरियाणा सरकार ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को सरकारी कामकाज से अस्थायी रूप से समिति से बाहर (डी-एम्पैनल्ड) कर दिया है। यह कदम दोनों बैंकों पर धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनजर उठाया गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि उसके द्वारा खोले गए सरकारी खाते सभी आवश्यक केवाईसी जांच और प्राधिकरण प्रक्रिया के अनुरूप थे। बैंक ने यह भी कहा कि उसके पास पूर्ण ऑडिट ट्रेल और सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें संबंधित सरकारी विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। सरकारी खाते में पहले 25 करोड़ रुपये की राशि एक बड़े निजी बैंक से स्थानांतरित की गई। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 47 करोड़ रुपये 14 लेनदेन के माध्यम से प्राप्त हुए। बैंक ने कहा कि सभी लेनदेन सरकारी विभाग के निर्देशानुसार और सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत किए गए। बैंक ने बताया कि खाता 15 जनवरी 2026 को बंद कर दिया गया और शेष राशि मूल बैंक को ब्याज सहित लौटा दी गई। आंतरिक जांच जारी है और कुछ कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाया गया। बैंक ने कहा कि प्रारंभिक समीक्षा में किसी वित्तीय नुकसान या धोखाधड़ी का संकेत नहीं मिला। 17 फरवरी 2026 तक बैंक में हरियाणा सरकार की जमा राशि 735 करोड़ रुपये थी, जो 21 फरवरी तक घटकर 538 करोड़ रुपये रह गई। बैंक ने पारदर्शिता और सरकारी धन की सुरक्षा पर जोर देते हुए पुनः समिति में शामिल होने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखी है।

क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ खुला

- मीडियम-लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अवसर

नई दिल्ली । क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का आईपीओ सोमवार, 23 फरवरी से खुल गया है और यह 25 फरवरी तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 20 फरवरी को लगी थी। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,000 से 1,053 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। निवेशक कम से कम 14 शेयरों का एक लॉट खरीद सकते हैं, जिससे एक लॉट की कीमत लगभग 14,742 रुपए होगी। शेयर 2 मार्च 2026 को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होने की संभावना है। कंपनी कुल 3,100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू शामिल है, जिसके तहत लगभग 1.14 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 1,900 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) होगा, जिसमें प्रमोटर बीजीटीएफ वन होल्डिंग्स और केएमपीआईएनसी एलएलपी अपने शेयर बेचेंगे।

होली पर 80 हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद, देसी उत्पादों की धूम

- पिछले साल के 60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 25 फीसदी ज्यादा

मुंबई ।

इस साल होली देशभर के व्यापारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कॉन्फेडरेशन आफ आल इं डिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार इस बार त्योहार के मौके पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है, जो पिछले साल के 60,000 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 25 फीसदी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब बाजारों में साफ नजर आ रहा है। अब होली के रंग, पिचकारियां और सजावटी सामान स्थानीय कारीगरों और स्वदेशी उत्पादों से भरे बाजारों में मिल रहे हैं। ग्राहकों में सेहत और त्वचा को लेकर जागरूकता बढ़ने से केमिकल रंगों की बजाय हर्बल और प्राकृतिक रंगों की मांग तेजी से बढ़ी है। बच्चों के लिए स्पाइडर-मैन और छोटा भीम वाली पिचकारियां खास आकर्षण बनी हैं। कपड़ों में सफेद टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा और प्रिंटेड टी-शर्ट की बिक्री बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक व्यापारिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कैट के अनुसार अकेले दिल्ली में 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। मिठाई की दुकानों पर गुजिया की मांग चरम पर है, और ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट आइटम्स और एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में भी तेजी है। त्योहार के दौरान सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी लाभान्वित हुआ है। दिल्ली में 3,000 से ज्यादा सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस और बड़े रेस्टोरेंट लगभग फुल बुक हैं।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को भारतीय 5 पैसे की बढ़त के साथ ही 90.94 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया 21 पैसे उछलकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.73 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क को बढ़ाकर 15 फीसदी करने की आशंकाओं के बीच डॉलर के कमजोर होने से घरेलू मुद्रा को बल मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.76 पर खुला और फिर 90.73 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की बढ़त दिखाता है। रुपया शुक्रवार को 26 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.94 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 97.47 पर रहा।

बिटकॉइन 64,300 डॉलर पर फिसला, क्रिप्टो मार्केट में गिरावट

- 65,000 डॉलर के नीचे लुढ़का भाव

मुंबई । दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 65,000 डॉलर के अहम स्तर से नीचे फिसलकर लगभग 64,300 डॉलर पर आ गई। यह पिछले आठ महीनों का सबसे निचला स्तर है। काइन मार्केट कैप के आंकड़ों के अनुसार, बिटकॉइन में गिरावट लगभग 4.8 फीसदी दर्ज की गई। इसी तरह, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथे रियम 5 फीसदी से अधिक टूट गई। इसके अलावा, प्रमुख टोकन जैसे एक्सआरपी और बाइनेंस काइन में भी 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। स्टेबलकॉइन टेथर लगभग 1 डॉलर पर स्थिर रहा। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित 15 फीसदी ग्लोबल टैरिफ ने निवेशकों को जोखिम संपत्तियों से दूर रहने पर मजबूर किया। इससे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने आईईईपीए के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ को रद्द किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में नए शुल्क लागू कर दिए गए। इस अप्रत्याशित कदम ने बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी। बाजार में जोखिम से बचाव की रणनीति अपनाते हुए निवेशक अब सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर झुक रहे हैं, जहां लगभग 2 फीसदी की तेजी देखी गई। मुद्रेक्स के क्वांट विश्लेषकों का कहना है कि क्रिप्टो ईटीएफ से लगातार निकासी भी बिकवाली को तेज कर रही है। इस वजह से सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री प्रभावित हुई। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप घटकर लगभग 2.23 ट्रिलियन डॉलर रह गया।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 479, निफ्टी 141 अंक उछला

मुंबई।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आई है। सकारात्मक वैश्विक संकेत, विदेशी निवेशकों की वापसी और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती से भी बाजार को समर्थन मिला है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स479.95 अंकों की बढ़त के साथ ही 83,294.66 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 141.75 अंक बढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। आज । निफ्टी मिडकैप 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई स्मॉलकैप 0.29 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ आज निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर शेयरों में भी तेजी रही। वहीं निफ्टी आईटी में सबसे अधिक गिरावट रही। इसके अलावा निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स भी फिसला।

सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो अदाणी पोर्ट्स, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये सबसे अधिक लाभ वाले शेयरों की सूची में शामिल रहे। वहीं, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व और आईटीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

इस तरह, भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में लगातार दूसरे सत्र में बढ़त रही। पीएसयू बैंक और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी से बाजार धारणा मजबूत हुई । इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ आये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बाजार में उत्साह का माहौल है। इससे पहले सुबह बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। संबह सेंसेक्स 100 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 82,906 पर खुला। वहीं निफ्टी भी मजबूती के साथ 25,678 अंक पर खुला। सुबह शुरुआत के बाद निफ्टी 149.10 अंक की बढ़त के साथ 25,720 पर कारोबार कर रहा था।

वहीं पिछले दिन शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 316.57 अंक उछलकर 82,814.71 अंक पर बंद हुआ था, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 116.90 अंक की बढ़त के साथ 25,571.25 पर बंद हुआ था।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ की धोखाधड़ी, शेयर 20 फीसदी तक लुढ़के

- निवेशकों के डूबे 14,000 करोड़, बैंक का मार्केट कैप घटकर 57,485.60 करोड़ रह गया

मुंबई।

चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक शाखा में लगभग 590 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी सामने आई है। बैंक के अनुसार शाखा के कुछ कर्मचारी हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में बिना अनुमति के लेनदेन कर रहे थे, जिससे जमा राशि में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ। यह राशि बैंक की तिमाही कमाई से भी अधिक बताई जा रही है। इस घटना से बैंक के शेयरों और निवेशकों को बड़ा झटका लगा। सोमवार को एनएसई पर शेयर 20 फीसदी तक गिरकर 67 रुपए के लोअर सर्किट पर पहुंच गए। बैंक का मार्केट कैप 71,854.85 करोड़ से घटकर 57,485.60 करोड़ रुपए रह गया, यानी एक ही दिन में लगभग 14,369 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह मार्च 2020 के बाद बैंक के शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। धोखाधड़ी तब उजागर हुई जब हरियाणा सरकार ने अपने खातों को बंद कर राशि अन्य बैंक में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। मिलान प्रक्रिया के दौरान बैंक रिकॉर्ड और सरकारी विभागों द्वारा बताई गई राशि में अंतर पाया गया। 18 फरवरी 2026 के बाद अन्य सरकारी संस्थानों से संपर्क करने पर और विसंगतियां सामने आईं।

बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी से फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया। दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संदिग्ध खातों में जमा रकम पर रोक लगाने के लिए संबंधित बैंकों से संपर्क किया गया। बैंक का कहना है कि मामला केवल चंडीगढ़ शाखा और कुछ सरकारी खातों तक सीमित है, अन्य ग्राहकों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा। निवेशक अब जांच की प्रगति और बैंक की अगली रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ठाणे में 18 एकड़ की नई आवासीय परियोजना बनाएगा

भूस्वामी के साथ की साझेदारी, 7500 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य

नई दिल्ली। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने मुंबई क्षेत्र में अपने विस्तार के तहत ठाणे में 18 एकड़ के भूखंड के विकास के लिए संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह परियोजना मुख्य रूप से आवासीय होगी और इससे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का संभावित राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने भूस्वामी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज रणनीतिक रूप से जमीन की सीधी खरीद और भूस्वामी के साथ संयुक्त विकास दोनों मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी का कहना है कि उच्च संभावनाओं वाले सूक्ष्म बाजारों में विस्तार उसकी वृद्धि रणनीति का अहम हिस्सा है और इसका उद्देश्य मकान खरीदारों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण करना है। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि ठाणे मुंबई महानगर क्षेत्र का सबसे आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। यह परियोजना ठाणे में कंपनी की चौथी परियोजना होगी, जिससे क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और मजबूत होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में कंपनी की बिक्री बुकिंग 25 फीसदी बढ़कर 24,008 करोड़ रुपए हुई।

स्कोडा की नई रणनीति, काइलैक से सीएनजी और ईवी में बदलाव

लॉन्च होने के बाद काइलैक की बिक्री 50,000 यूनिट से अधिक हो चुकी

नई दिल्ली। स्कोडा आटो इंडिया की कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक ब्रांड के विकास का प्रमुख आधार बन चुकी है। 2025 की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद काइलैक की बिक्री 50,000 यूनिट से अधिक हो चुकी है और 2026 में भी इसी गति के बनाए रखने की संभावना है। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी के अनुसार, काइलैक अब कंपनी की कुल बिक्री में लगभग 60 फीसदी योगदान देती है। समूह स्तर पर स्कोडा आटो वोक्सवेगन इं डिया की कुल बिक्री में इस श्रेणी का 40 फीसदी हिस्सा है। कंपनी फैक्टरी-फिटेड सीएनजी मॉडल पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का लगभग 20 फीसदी हिस्सा पहले से ही सीएनजी पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि थर्ड-पार्टी रेट्रोफिट के विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा और कोई भी सीएनजी पेशकश फैक्टरी में तैयार होगी। हालांकि लॉन्च की सटीक समय-सीमा नहीं बताई गई, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि सीएनजी वेरिएंट जल्द ही उपलब्ध हो सकता है। ईवी के मामले में कंपनी सतर्क दृष्टिकोण अपनाए हुए है। उनका कहना है कि भारत में मुख्य खिलाड़ी बनने के लिए ईवी पोर्टफोलियो आवश्यक है। फोकस भारत में बनी ईवी पर है, जिसमें निर्यात की संभावना भी शामिल है। यूरोपीय ईवी का सीमित आयात रणनीतिक रूप से उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। आगामी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फेज-3 मानदंड उत्सर्जन लक्ष्यों को कड़ा करेंगे। ऐसे में सीएनजी और ईवी में विस्तार अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि व्यापक बाजार वाली श्रेणियों में बिक्री बढ़ने पर उत्सर्जन संतुलन के लिए आवश्यक बन गया है।

जीडीपी का नया आधार वर्ष, डब्ल्यूपीआई को लेकर मतभेद

- वास्तविक वृद्धि के आकलन में गड़बड़ी की आशंका

नई दिल्ली । भारत इस शुक्रवार से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अधिक समकालीन, सटीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर मतभेद है कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का आधार वर्ष 2011-12 ही बने रहने से वास्तविक (रियल) वृद्धि के अनुमान प्रभावित हो सकते हैं या नहीं। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है, लेकिन डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष अब तक संशोधित नहीं हुआ है। डब्ल्यूपीआई के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय संकलित करता है और राष्ट्रीय लेखा में इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों के उत्पादन को डिफ्लेट करने के लिए किया जाता है। बाजार के जानकारों ने डब्ल्यूपीआई को राष्ट्रीय लेखा की सबसे कमजोर कड़ी बताया है। उनका कहना है कि भले ही सूचकांक की टोकरी और भार न बदले जाएं, आधार वर्ष का अद्यतन आवश्यक है ताकि नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच विसंगतियां न पैदा हों। उन्होंने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के रुझानों में तालमेल की कमी पर भी चिंता जताई। वहीं भारत के एक सांख्यिकीविद् का मानना है कि डब्ल्यूपीआई का उपयोग उद्योग-विशेष स्तर पर किया जाता है और इसका प्रभाव समग्र जीडीपी पर सीमित हो सकता है। उनके अनुसार, अद्यतन डेटा होना बेहतर है, लेकिन स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी आउटडेटेड सीपीआई के मामले में होती। नई जीडीपी श्रृंखला में विनिर्माण क्षेत्र के लिए डबल डिफ्लेशन पद्धति लागू की जा सकती है, जिससे उत्पादन और लागत को अलग-अलग समायोजित कर अधिक सटीक वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया जा सके।

टैरिफ बढ़ोतरी से सोना और चांदी में जोरदार उछाल

- सोना 1.60 लाख पार, चांदी भी 2,63,061 रुपए किलो

नई दिल्ली ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बाद सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है, जिसका असर सोना और चांदी के वायदा भाव पर साफ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुओं ने आज तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। मल्टी कमो डिटी एक्सचेंज आफ इं डिया (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 1,582 रुपये की तेजी के साथ 1,58,458 रुपये पर खुला। पिछला बंद भाव 1,56,876 रुपये था। फिलहाल सोना 3,173 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,049 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसने 1,60,600 रुपये का दिन का उच्च स्तर और 1,58,117 रुपये का निचला स्तर छुआ। इस साल सोना 1,80,779 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। चांदी के मार्च वायदा कॉन्ट्रैक्ट में भी मजबूती रही। यह 10,117 रुपये की तेजी के साथ 2,63,061 रुपये पर खुला। बाद में 14,729 रुपये की बढ़त के साथ 2,67,673 रुपये पर कारोबार करता दिखा। चांदी ने दिन में 2,67,929 रुपये का उच्च और 2,63,061 रुपये का निचला स्तर छुआ। इस वर्ष चांदी 4,20,048 रुपये प्रति किलो के शिखर तक पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती का रुख है। कॉमेक्स पर सोना 5,128.80 डॉलर प्रति औंस पर खुला और बाद में 5,188.20 डॉलर तक पहुंच गया। वहीं चांदी 84.60 डॉलर पर खुलकर 87.11 डॉलर प्रति औंस तक चढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ बढ़ोतरी से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे सोना-चांदी को मजबूत समर्थन मिल रहा है।

रूस के तेल पर प्रतिबंधों का असर, भारत का कच्चा तेल आयात बदलते संतुलन की ओर

मुंबई ।

भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात धीरे-धीरे घट रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में रोजाना लगभग 1.09 मिलियन बैरल तेल रूस से आया, जो जनवरी के 1.22 मिलियन बैरल से 10 फीसदी कम है। शिपिंग डेटा और विशेषज्ञों के अनुसार मार्च में यह और घटकर 8-10 लाख बैरल प्रतिदिन रह सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से डिस्काउंट पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था, लेकिन अब वह दौर धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण रूस से आयात बढ़ाना सीमित है। रूस से घटती सप्लाई की जगह मध्य पूर्व के देश भर रहे हैं। सऊदी अरब फरवरी में भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, जहां से रोजाना 1-1.1 मिलियन बैरल तेल मिलने की उम्मीद है। महीने के आंकड़े अभी तक 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जा चुके हैं।

मार्च की शुरुआत में थोड़ी कमी की संभावना है। इसके बाद रूस और इराक क्रमशः सप्लाई देंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने इराक को पछाड़कर भारत के कुल आयात का लगभग 40 फीसदी हिस्सा ले लिया था, लेकिन अब यह हिस्सा घट रहा है। फरवरी के पहले 18 दिनों में भारत का औसत आयात 4.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो जनवरी के 5.25 मिलियन बैरल से 8 फीसदी कम है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में उतार-चढ़ाव केवल कीमतों से नहीं बल्कि सैंक्शन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से आएगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 विश्व कप: टी20 विश्वकप के सुपरआठ में आज होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला

पल्लीकेली (एजेंसी)। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट के सुपर-आठ में मंगलवार को आमने-सामने होंगी। इस मैच में दोनो ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। इंग्लैंड ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को हराया है जिससे उसके हौंसले बुलंद हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम का पहला मुकाबला न्यूलीलैंड से बारिश के कारण नहीं हो पाया था। अब तक इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है।ऐसे में वह खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। कोलंबो की पिच से धीमे गेंदबाजों को सहायता मिलने की उम्मीद है। पहले ही मैच में श्रीलंका पर 51 रनों की जीत से इंग्लैंड का रन रेट भी बेहतर हुआ है और वह ग्रुप में शीर्ष पर है।

इंग्लैंड को हालातों का भी लाभ मिले। उसने हाल ही में इसी जगह पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेला था। वहीं सुपर 8 मैच में श्रीलंका को हराया था, जिससे उन्हें मुकाबले से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी बेहद कमजोर है, अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम अब तक असफल रहे हैं। साहिबजादा फरहान के अलावा एक भी बल्लेबाज फार्म में नहीं है। पाक टीम उस्मान तारिक सहित अपने धीमे स्पिनरों के जरिये इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। टीम के पास उस्मान के अलाव सैम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे गेंदबाज हैं।

ये पाकिस्तानी गेंदबाज इंग्लैंड की बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने का पूरा प्रयास करेंगे। खेल के आखिरी स्टेज में पिच और धीमी होने की संभावना है। गेंदबाजों के पक्ष में हालात होने के कारण इस मुकाबले में स्पिन मैच का परिणाम तय करेंगे।

अब तक के आंकड़ों में इंग्लैंड की टीम हावी रही है। दोनो के बीच अब तक 31 मुकाबले हुए हैं। इसमें से इंग्लैंड ने 31 जबकि पाक ने केवल 9 मैच ही जीते हैं।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

इंग्लैंड : हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ल्यूक वुड।

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब,

शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

पाक स्पिनर तारिक के एक्शन को लेकर दो खेमों में बंटे दिग्गज, अंपायर चौधरी ने भी उठाये सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी टी20 विश्वकप में इस बार पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक अपनी विवादस्पद गेंदबाजी के कारण निशाने पर हैं। तारिक गेंदबाजी के दौरान ही बीच में रुक जाते हैं जिससे बल्लेबाज संशय में फंस जाते हैं। उनके गेंदबाजी एक्शन पर कई दिग्गज क्रिकेटरों ने सवाल उठाये हैं हालांकि अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इस गेंदबाज पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में क्रिकेट जगत दो गुटों में बंट गया है। एक का मानना है कि तारिक की गेंदबाजी जादुई है वहीं दूसरे गुट का मानना है जिस प्रकार से ये गेंदबाज पूरी बांह वाली टी शर्ट पहनकर गेंदबाजी कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आईसीस नॉकआउट मुकाबलों से पहले आईसीसी को इस गेंदबाज के एक्शन की जांच करनी चाहिये।

अंपायर अनिल चौधरी ने भी इस स्पिनर के एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंखिर वह पूरी बांह वाली टी-शर्ट ही क्यों पहने रहता है ? साथ ही कहा कि तारिक का मैदान पर और मैदान के बाहर हमेशा फुल टी-शर्ट पहनना समझ से परे है। इसके पीछे कुछ राज है। साथ ही कहा, 'जब कोई गेंदबाज भीषण गर्मी में भी अपनी आस्तीन नीचे नहीं करता और अभ्यास सत्र में भी हाफ टी-शर्ट पहनने से बचता है, तो मन में आशंका होना स्वाभाविक है। वह अपनी कोहनी के पास से क्या छुपाना चाहता है। हमने पहले भी देखा है कि संदिग्ध एक्शन वाले गेंदबाज कोहनी के मुड़ाव को छिपाने के लिए पूरी बांह की टी शर्ट पहनने रहे हैं। चौधरी के सोशल मीडिया पर उठाये इस सवाल के बाद पाक स्पिनर के एक्शन को लेकर बहस तेज हो वहीं एक दिग्गज पूर्व विकेटकीपर ने कहा कि इस गेंदबाज का बचाव करते हुए कहा कि उसकी गेंदबाजी में जो विविधता है, वो लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिली है. उन्होंने कहा, 'उनकी गेंद को विकेट के पीछे से देखना काफी अच्छा अनुभवी है। वो जिस तरह से फ्लाइट देते हैं और अचानक गेंद को तेज़ी से टर्न कराते हैं, वो काबिले-तारीफ है। अंपायरों को सबूतों पर बात करनी चाहिए, सिर्फ कपड़ों पर नहीं। इस बार पाक के सुपर-8 में पहुंचने में तारिक की अहम भूमिका रही है। उन्होंने अहम मौकों पर बड़े विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। इस गेंदबाज ने अभी तक किसी भी बायोमैकेनिकल टेस्ट में अपनी कोहनी की जांच नहीं करायी है। ऐसे में अगर जांच में उनकी कोहनी 15 डिग्री से अधिक मुड़ती दिखी तो उनपर प्रतिबंध लगना तय है।

भारत और जिम्बाब्वे में विश्वकप फाइनल देखना चाहते हैं द्रविड़

मुंबई (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के अनुसार भारतीय टीम विश्वकप फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार है। द्रविड़ के अनुसार इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सबसे अधिक सकारात्मक बात ये है कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर रही है। टीम में गहरायी है और उसका हर खिलाड़ी मैच का रुख मोड़ सकता है। साथ ही कहा कि दूसरी टीम के तौर पर अगर जिम्बाब्वे से फाइनल में भारत का मुकाबला होता है तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे ने इस बार काफी अच्छा खेल देखाया है और वह भी फाइनल में खेलने की दावेदार बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को अपनी मैच योजनाओं पर बने रहना चाहिए।

द्रविड़ ने से कहा, 'मुझे लगता है कि हम कुछ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास टीम में गहराई है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह गहराई निखरकर सामने आएगी। टी20 क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता है। यह खेल का सबसे अस्थिर फॉर्मेट है, और किसी भी दिन, जैसा मैंने कोच के रूप में भी सीखा है, आप हार सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं रहो, जो कर सकते हो करो और अच्छे की उम्मीद करो,।' टी20 विश्वकप में इस बार जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में जिस प्रकार से हराया है,उससे उसके हौंसले बुलंद हैं। इसके बाद उसने श्रीलंका को भी हराया। द्रविड़ ने कहा, 'अगर यह जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंचता है तो उसके क्रिकेट के लिए ये अच्छा अनुभव होगा। अगर जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंचता है तो यह काफी अच्छा होगा। मैं चाहूंगा कि भारत के साथ कोई छोटी टीम भी फाइनल में पहुंचे। यह बहुत अच्छा होगा।' द्रविड़ ने कहा कि इस बार एसोसिएट देशों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सभी टेस्ट देशों को कड़ी टक्कर दी है। पाकिस्तान को नीदरलैंड्स से जबकि भारत को अमेरिका ने कड़ी टक्कर दी। उन्होंने कहा कि इस बार जिस प्रकार छोटी टीमों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बड़ी टीमों को अच्छी चुनौती दी उससे मुकाबलों का रोमांच बढ़ गया है। जिस प्रकार से इन टीमों ने खेला है,उससे मुझे काफी अच्छा लगा। इससे एसोसिएट देशों की प्रतिभा सामने आ रही है। इन सभी टीमों ने अच्छी अच्छा खेला है हालांकि मामुली अंतर से ये सुपर-8 में क्वालिफाई न कर पायी हैं पर भविष्य इनका काफी अच्छा है। इन टीमों के पास कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।

टी20 विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका से शर्मनाक हार के बाद चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, अब करो या मरो का मुकाबला

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सोमवार को चेन्नई पहुंच गई। टीम 26 फरवरी को एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के अपने दूसरे मैच के लिए चेन्नई में तैनात है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के पहले सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा।

इस बड़ी हार के साथ ही भारत को आईसीसी क्रिकेट के सभी श्वेत-गेंद प्रारूपों में 18 मैचों में पहली हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले 2023 विश्व कप के फाइनल में भी भारत को इसी मैदान - नरेंद्र मोदी स्टेडियम - पर ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। टी20

अंतरराष्ट्रीय मैचों में रनों के अंतर से यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार थी। इससे पहले 2019 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों की हार हुई थी। टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

मैच की बात करें तो, डेविड मिलर (63) और देवाल्ड ब्रेविस (45) की चौथी विकेट के लिए शानदार 97 रनों की साझेदारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवरों में 187/7 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने तेज गति से खेलते हुए नाबाद 44 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह (2/28), जसप्रीत बुमराह (3/15), वरुण चक्रवर्ती (1/47) और शिवम दुबे (1/32) ने विकेट लिए। 188 रनों का बचाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। भारतीय बल्लेबाजों में से कोई भी अर्धशतक नहीं बना सका। शिवम दुबे ने 42 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया और भारत ने मौजूदा चैंपियन को 18.5 ओवरों में मात्र 111 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम को 76 रनों से हरा दिया।

भारत के लिए अर्शदीप सिंह (2/28), जसप्रीत बुमराह (3/15), वरुण चक्रवर्ती (1/47) और शिवम दुबे (1/32) ने विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान एडेन मार्कराम (1/5), मार्को जानसेन (4/22), केशव महाराज (3/24) और कॉर्बिन बॉश (2/12) ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया।

अब हमारा लक्ष्य टी20 विश्वकप जीतना : मंधाना

केनबरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली सफलता से टीम का मनोबल बढ़ा है और अब उसका लक्ष्य आगामी टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतना है। महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से पांच जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। मंधान ने कहा है टीम काफी अच्छा खेल रही है और उसकी सभी खिलाड़ी लय में हैं। टीम ने जिस प्रकार से एकदिवसीय विश्वकप जीता था, उसी तर्ज पर अब वह टी20 विश्वकप जीतना चाहती है। मंधाना ने कहा ''मुझे लगता है कि हम एक ऐसे बदलाव के दौर में हैं जहां हम विश्व क्रिकेट पर अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं। हम किसे हराते हैं, कहां हराते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस उन्हें लगातार हराने और शीर्ष पर बने रहने में सफल होना चाहते हैं।''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मंधाना ने 82 रन रन बनाये जिससे भारतीय टीम को आसानी से जीत मिली। मंधाना ने कहा, ''मुझे एडिलेड शहर बहुत पसंद है। यहां खेलने से पहले भी मुझे यहां शहर पसंद था। यह बहुत शांत और सुंदर शहर है।।''

वरुण ने अर्शदीप का रिकार्ड तोड़ा : लगातार 18 पारियों में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने

अहमदाबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में एक विकेट लेते ही एक नया रिकार्ड बनाया है। वरुण अब लगातार 18 पारियों में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गये हैं। वरुण लगातार 18 पारियों में भारत के लिए विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पीछे छोड़ा। अर्शदीप सिंह ने साल 2024-25 में लगातार 17 पारियों में विकेट लेने का रिकार्ड बनाया था। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 2025-26 के बीच अब तक कुल 18 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इसी सूची में तीसरे नंबर पर पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा है। नेहरा ने साल 2016 में 13 पारियों में एक या उससे अधिक विकेट लिए थे।

भारतीय टीम की हार से गंभीर की लचर रणनीति पर फिर उठे सवाल

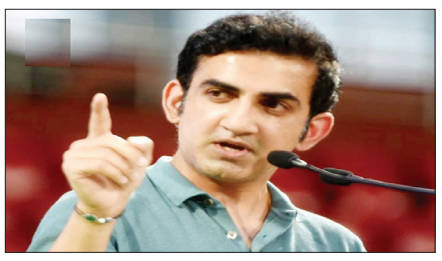

अहमदाबाद। टी20 विश्वकप क्रिकेट के सुपर आठ के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की करारी हार के लिए खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के साथ ही कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि टीम के खराब प्रदर्शन के लिए गंभीर की लचर योजनाएं भी जिम्मेदार हैं।

मैच केवल मैदान पर नहीं खेला जाता बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिमाग में खेला जाता है। टीम प्रबंधन ने यहां गलती कर दी। इसी कारण ग्रुप स्तर पर सभी मैच जीतने वाली टीम धीमी और काली मिट्टी के विकेट पर विफल रही। इस मैच में अंगुल के स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज सहज नहीं दिखे। न तो भारतीय टीम प्रबंधन की योजनाओं में स्पष्टता दिखी और न वह उन्हें अमल में ला पायी। यहां तक की पारी की शुरुआत कौन करेगा। ये भी अंत तक तय नहीं था। गंभीर अपने सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ी उतारने की बजाय लगातार प्रयोग करते दिखे। वह भी ऐसे समय तब कि एक ही टीम उतारी जानी चाहिये। मैच में उपकप्तान अक्षर पटेल की जगह पर अंतिम ग्यारह में वाशिंगटन सुंदर को उतरा गया। सुंदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनो में विफल रहे। टीम में चयनित खिलाड़ी को ही अंत तक पता नहीं होता है कि वह अंतिम ग्यारह में है कि नहीं। इससे उनकी तैयार भी प्रभावित होती है जबकि विश्वकप खेलते समय टीम पहले से ही तय कर ली जाती है और वही पूरे समय खेलती है।

एफआईएच प्रो लीग: स्पेन के खिलाफ आज जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी टीम इंडिया, साख दांव पर

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में जुझारु प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम मंगलवार को यहां स्पेन के खिलाफ होने वाले मैच में वापसी करके एफआईएच प्रो लीग में अपने अभियान को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। नौ टीमों के इस टूर्नामेंट में अब तक भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। राउरकेला और होबार्ट में खेले गए दोनों चरणों में भारत को पांच हार का सामना करना पड़ा जबकि एक मैच उसने ड्रॉ खेला।

कोच क्रेग फुल्टन आलोचनाओं का सामना कर रहे

टीम के इस लचर प्रदर्शन के कारण कोच क्रेग फुल्टन पर दबाव बढ़ गया है जो लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। नियमित कप्तान हरमनप्रीत सिंह के व्यक्तिगत कारणों से होबार्ट चरण से हटने के बाद युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह को कप्तानी सौंपी गई। होबार्ट चरण में स्पेन से पहला मैच 0-2 से हारने के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया था लेकिन उसे पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम हालांकि इस मैच से वर्तमान टूर्नामेंट का पहला अंक हासिल करने

में सफल रही थी।

भारतीय टीम अब स्पेन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इन दोनों टीमों के बीच वर्षों से कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को समान रूप से टक्कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत एक समय जीत की स्थिति में था। अमित रोहिदास और जुगराज सिंह के गोल की बदौलत भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन मैच के अंत में गोल खाने की वही पुरानी समस्या फिर से सामने आ गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार वापसी करते हुए पेनल्टी शूटआउट में मैच जीत लिया।

इससे पहले राउरकेला में खेले गए चारों मैचों में भारत की हार को देखते हुए इस टीम का अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। राउरकेला में भारत को अर्जेंटीना से 0-8 की करारी शिकस्त भी मिली थी। पिछले मैच में शिलानंद लाकड़ा ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उनकी तेज दौड़ और रिवर्स-हिट ने ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर को चकमा दे दिया, हालांकि बैक-स्टिक के इस्तेमाल के कारण उनके इस गोल को अमान्य घोषित कर दिया गया। युवा आदित्य ललागे ने भी अपनी छाप छोड़ी। भारतीय टीम को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अब अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा क्योंकि नौ टीमों वाली एफआईएच प्रो लीग तालिका में वह छह मैचों में सिर्फ एक अंक के साथ आठवें स्थान पर है। भारत के पीछे केवल पाकिस्तान है जिसने अब तक अपने सभी आठ मैच हारे हैं और अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। होबार्ट चरण में भारतीय टीम स्पेन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेलेगी।

इसके बाद जून में यूरोप में मुकाबले होंगे, जहां भारत नीदरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड में खेलेगा। लेकिन उससे पहले भारत का तात्कालिक लक्ष्य अंक हासिल करना और तालिका में आगे बढ़ना होगा। बेल्जियम (आठ मैच, 22 अंक) तालिका में अभी सबसे आगे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (सात मैच, 20 अंक) और अर्जेंटीना (आठ मैच, 17 अंक) का नंबर आता है। जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले एफआईएच प्रो लीग में दमदार प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा। एशियाई खेल लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाइंग टूर्नामेंट भी है।

किदांबी श्रीकांत जर्मन ओपन में भारतीय चुनौती की करेंगे अगुवाई

मुलहेम एन डेर रूर (जर्मनी)। दुनिया के पूर्व नंबर वन किदांबी श्रीकांत मंगलवार से मुलहेम एन डेर रूर के वेस्टएनर्जी स्पोटहॉल में शुरू होने वाले जर्मन ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती अगुवाई करेंगे। पुरुषों की एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 32वें स्थान पर काबिज किदांबी श्रीकांत, इस साल की शुरुआत में इंडिया ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स में दो क्वार्टर-फाइनल से बाहर होने के बाद जर्मन ओपन में उतरेंगे। उन्हें आखिरी बार इस महीने की शुरुआत में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में खेलते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने भारत के लिए अपने दोनों एकल रबर जीते थे। पुरुषों के एकल मुख्य ड्रॉ में किदांबी श्रीकांत के साथ उनके हमवतन किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली भी होंगे। ओलंपियन और दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव पुरुष एकल में टॉप सीड हैं और पहले राउंड में किरण जॉर्ज से भिड़ेंगे। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु की गैरमौजूदगी में दुनिया की नंबर 40 तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स में भारत की कमान संभालेंगी। तन्वी शर्मा, जो पिछले साल BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और यूएस ओपन में उप विजेता रही थीं, उनके साथ महिला एकल के मुख्य ड्रॉ में तस्नीम मीर, मालविका बंसोड़, रक्षिता रामराज और इशारानी बरुआ होंगी। महिला युगल के मुख्य ड्रॉ में भारत की अकेली जोड़ी अश्विनी भट और शिखा गौतम हैं।

सूर्यकुमार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार पर निराश जताई, बोले अगले मैचों से वापसी करेंगे

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में मिली हार पर निशाना जताते हुए कहा कि उनकी टीम अगले मैच के साथ ही अच्छी वापसी करेगी। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है जिससे उसके आगे के सफर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब भारतीय टीम को अपने बचे हुए दोनो ही सुपर-8 बैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। हार के बाद सूर्यकुमार ने प्रशंसकों को टूर्नामेंट में वापसी का भरोसा दिया।

मैच के बाद उन्होंने कहा, 'जब हमने मैच शुरू किया तब से ही हमे उसमें बने हुए थे। हमने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की पर बीच के ओवरों में विरोधी टीम ने अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी स्थित सुधार ली। उसके बाद भी हमारे गेंदबाजों ने विरोधी टीम को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। उसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए हम अच्छी शुरुआत नहीं कर पाये। साथ ही कहा कि आप पावरप्ले में गेम नहीं जीत सकते पर अपनी गलतियों से हार सकते हैं और यही इस मैच में हुआ। हमने पावरप्ले में कई विकेट खोए और उसके बाद हम छोटी-छोटी साझेदारी भी नहीं बना पाए हालांकि ये सब सब कुछ खेल का हिस्सा होता है। हम इससे सबक लेते हुए अगले मैच में गलतियों से बचेंगे। हमारा लक्ष्य बचे हुए दोनो ही मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाना रहेगा।'

इस मैच मे दक्षिण अफ्रीका से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रन ही बना पायी। भारत की ओर से शीर्ष क्रम असफल् रहा केवल शिवम दुबे ही 42 रन बना पाये। वहीं अन्य बल्लेबाज 20 रनों से अधिक नहीं बना पाये। वहीं दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस ने 45 रन बनाये। इन दोनो के बीच 97 रनों की साझेदारी से दक्षिण् अफ्रीका एक अच्छा स्कोर बनाने में सफल रही। ने 20 रन पर तीन विकेट

सूर्यकुमार ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की अच्छी गेंदबाजी की सराहतना की। उन्होंने कहा,हर कोई जानता है कि इन दोनो की गेंदबाजी कितनी घातक रही है। दोनों ने आठ ओवर गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लिए और केवल 45 से 50 रन दिए। बुमराह ने 15 रन पर देकर तीन विकेट जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन पहले ही ओवर में शून्य पर आउट हो गए। दूसरे ओवर में तिलक वर्मा भी पेवेलियन लौट गये। अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता तो खोल पाए पर अधिक नहीं टिक पाये। इसके बाद बाकि बल्लेबाज भी एक के बाद एक पेवेलियन लौट गये। इस मैच में जीत से दक्षिण अफ्रीका को 2 अंक मिले हैं जबकि भारतीय टीम को एक भी अंक नहीं मिला।

विश्वकप अंक तालिका में पाकिस्तान से भी पिछड़ी भारतीय टीम

मुम्बई। आईसीसी टी20 विश्वकप में ग्रुप स्तर पर धमाकेदार प्रदर्शन कर शीर्ष पर रही भारतीय टीम सुपर-आठ के पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों करारी हार के बाद अंक तालिका में पिछड़ती दिख रही है। इससे उसके सेमीफाइनल की उम्मीदें भी कम हो रही हैं। पहले सुपर-8 मैच के बाद भारतीय टीम पाकिस्तान से भी पीछे है। न्यूजीलैंड से पहला सुपर-8 मुकाबला बारिश की वजह से रद् होने के बाद पाक को एक 1 अंक मिला है पर भारतीय टीम के पास एक भी अंक नहीं है। ऐसे में एक और हार से वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अंतिम चार में जगह बनाने के लिए अब भारतीय टीम को अपने बाकी दो सुपर 8 मुकाबलों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. भारतीय टीम अपना दूसरा सुपर 8 मुकाबला गुरुवार 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी. वहीं एक मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उतरेगी। अगर भारतीय टीम अपने शेष दो मैचों में से एक भी हार जाता है, तो उसका खिताबी सफर सुपर 8 स्टेज में ही समापत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट काफी नीचे चला गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ट्रंप अगले महीने जाएंगे चीन की यात्रा पर, टैरिफ पर रहेगा फोकस

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से दो अप्रैल तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ट्रंप अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस यात्रा की पुष्टि की। यह यात्रा ऐसे समय में घोषित की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ओर से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों (टैरिफ) को रद्द कर दिया है। इनमें चीन के खिलाफ लगाए गए कुछ शुल्क भी शामिल थे।

379 राजनीतिक कैदियों की जल्द रिहाई, विरोधी नेताओं को राहत

वेनेजुएला, एजेंसी। राजनीतिक कारणों से कैद 379 लोगों को इस सप्ताहांत रिहा किया जा सकता है। यह रिहाई हाल ही में पारित आम क्षमा कानून के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस कानून के तहत विपक्षी सदस्य, कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षक, पत्रकार और कई अन्य कैदियों को लाभ मिलेगा। विशेष आयोग के अध्यक्ष जॉर्ज अरेजा ने कहा कि 379 क्षमा आवेदन प्राप्त हुए हैं और शुक्रवार से शनिवार तक रिहाई की प्रक्रिया पूरी होगी। कानून के तहत हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और सैन्य विद्रोह में दोषी पाए गए लोग शामिल नहीं हैं। फोरो पेनाल के अध्यक्ष अल्फ्रेडो रोमेरो ने कहा कि यह असमान और असंवैधानिक है कि कुछ राजनीतिक कैदियों को बाहर रखा गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सभी राजनीतिक कैदियों पर कानून लागू होना चाहिए। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि यह कानून राजनीतिक नेताओं की सहिष्णुता बढ़ाने और देश में नए राजनीतिक मार्ग खोलने का संकेत है।

अमेरिकी दबाव में वेनेजुएला ने क्यूबा के सुरक्षा बलों को हटाया

वॉशिंगटन , एजेंसी। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार पर अमेरिका की ओर से लैटिन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वामपंथी गठबंधन को खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके कारण क्यूबा के सुरक्षा सलाहकार और डॉक्टर वेनेजुएला छोड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अपनी सुरक्षा के लिए वेनेजुएला के अंगरक्षकों को नियुक्त किया है।

लेबनान पर इस्राइली हमले में हिजबुल्ला नेता समेत 14 मरे

लेबनान, एजेंसी। लेबनान के पूर्वी बेका घाटी में इस्राइली हमले में हिजबुल्ला के वरिष्ठ नेता समेत 14 लोग मारे गए। हमले में कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान में हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर ईरान व अमेरिका के बीच तनाव के कारण पश्चिम एशिया में अशांति का खतरा बढ़ गया है।

अग्निकांड पीड़ितों के क्षतिग्रस्त घरों को खरीदेगी हांगकांग सरकार

हांगकांग, एजेंसी। हांगकांग की सरकार ने अग्निकांड के पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना का एलान किया है। इसके तहत लोगों से बुरी तरह जल चुके उनके अपार्टमेंट्स के मालिकाना हक खरीदने की पेशकश की गई है। सरकार का लक्ष्य प्रभावित लोगों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र करना है ताकि वे कहीं और अपनी पसंद का घर ले सकें। नवंबर 2025 में वांग फुक कोर्ट में आवासीय परिसर में लगी भीषण आग ने 1948 के बाद की सबसे बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 128 से अधिक लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए थे।

मधेश में मस्जिद के सामने बारात निकालने पर दंगा, घरों में की तोड़फोड़; दो पुलिसकर्मी समेत आठ घायल

नेपाल, एजेंसी। नेपाल के मधेश प्रदेश के सीमावर्ती रौतहट जिले के गौर नगरपालिका क्षेत्र में मस्जिद के सामने से बारात निकालने पर दंगा हो गया। दो समुदायों में झड़प के बाद आगजनी की घटनाएं शुरू हो गईं। पथराव और मारपीट में दो पुलिसकर्मी समेत आठ लोग घायल हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार दोपहर से अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाजवूद गौर के भीतरी इलाकों में तनाव बना हुआ है। आगजनी की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुक सकी हैं। प्रशासन के अनुसार, गौर नगरपालिका-6 स्थित सनगढ़ा गांव में बृहस्पतिवार शाम को मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। इसी दौरान मस्जिद के सामने से बारात निकली, जिसमें बाजे बज रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजा बजाए जाने पर आपत्ति जताई और बारात को रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान किसी ने एक वाहन में आग लगा दी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सैकड़ों दंगा पुलिस को इलाके में तैनात कर दिया।

संविधान मानिए, एकतरफा नहीं चल सकता टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप को नील कात्याल की खुली चुनौती

वॉशिंगटन, एजेंसी। नील कात्याल का कहना है कि अगर टैरिफ वाकई अच्छे और जरूरी हैं तो सरकार को कांग्रेस को मनाकर कानून के जरिए मंजूरी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान भी यही प्रक्रिया बताता है। इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या व्यापार घाटे को भुगतान संतुलन घाटा माना जा सकता है, जबकि आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञ इसे अलग-अलग मानते हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए नए वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। मशहूर भारतीय-अमेरिकी वकील नील कात्याल ने ट्रंप के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर राष्ट्रपति को इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाना है तो उन्हें संविधान के अनुसार कांग्रेस से मंजूरी लेनी चाहिए, न कि सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके ऐसा करना चाहिए।

ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का आधार कमजोर : कात्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप जिस कानून, ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122, का सहारा लेकर 15त्न तक का वैश्विक टैरिफ लगा रहे हैं, वह कानूनी तौर पर कमजोर आधार है। उन्होंने बताया कि पहले इसी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह धारा यहां लागू ही नहीं होती, क्योंकि व्यापार घाटा और भुगतान संतुलन घाटा दोनों अलग चीजें हैं। अब सरकार उसी धारा का इस्तेमाल कर रही है, जो खुद उसकी पहले की दलील से टकराता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया रद्द : यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि टैक्स लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास होता है और राष्ट्रपति ने आईईईपीए कानून का गलत इस्तेमाल किया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत नया रास्ता अपनाते हुए पहले 10त्न का वैश्विक टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 15त्न कर दिया गया। ट्रंप ने इसे अस्थायी आयात शुल्क बताया और कहा कि यह अमेरिका के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। कात्याल का कहना है कि अगर टैरिफ वाकई अच्छे और जरूरी हैं तो सरकार को कांग्रेस को मनाकर कानून के जरिए मंजूरी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान भी यही प्रक्रिया बताता है। इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या व्यापार घाटे को भुगतान संतुलन घाटा माना जा सकता है - जबकि आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञ इसे अलग-अलग मानते हैं।

पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने किया कात्याल का समर्थन इस बहस को और वजन तब मिला जब अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री और आईएमएफ की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी गीता गोपीनाथ ने भी कात्याल की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कात्याल इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स की बुनियादी बात समझा रहे हैं और सरकार का तर्क आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर लगता है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है असर इस बीच, इस फैसले का असर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि भारत समेत सभी देशों पर यह नया टैरिफ लागू होगा, जब तक कोई नया समझौता नहीं हो जाता। भारत सरकार ने कहा है कि वह इस पूरे घटनाक्रम का अध्ययन कर रही है और उसके असर का आकलन किया जा रहा है।

ईरान पर सीमित सैन्य हमले पर विचार कर रहे ट्रंप, खामेनेई व बेटे की हत्या का विकल्प

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने स्पष्ट किया, मैं कह सकता हूं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, हालांकि तेहरान के साथ किसी समझौते की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सीएनबीसी के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, इस पर वे 10 से 15 दिनों में फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान के साथ समझौता हो जाता है, तो सैन्य कार्रवाई टाली जा सकती है। हालांकि ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो वह जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए सीमित अमेरिकी हमलों से कहीं ज्यादा गंभीर होगा। परमाणु वार्ता में नहीं झुकेगा ईरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बीच उनका देश विश्व शक्तियों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

ट्रंप के सामने खामेनेई व बेटे की हत्या का विकल्प : ट्रंप के सामने सैन्य विकल्पों के रूप में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई की लक्षित हत्या जैसे विकल्प भी प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि, राष्ट्रपति ने फिलहाल ईरान पर हमले के मुद्दे पर फैसला नहीं लिया है। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष कई परिदृश्यों पर चर्चा की गई। इनमें से एक था- खामेनेई, उनके बेटे मोजतबा व अन्य मुल्लाओं को हमले में मार गिराना। मोजतबा को व्यापक रूप से उनके पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। तेल बाजार पर असर = कीमतें स्थिर, लेकिन जोखिम बरकरार ईरान पर संभावित अमेरिकी कार्रवाई की आशंका के बीच वैश्विक तेल बाजार सतर्क नजर आ रहा है। इस सप्ताह ट्रेडरों द्वारा सैन्य जोखिम को कीमतों में शामिल किए जाने के बाद तेल में 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई थी। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चा तेल 4 सेंट गिरकर 66.39 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 10 सेंट बढ़कर 71.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

मिडिल ईस्ट पर इस्राइल का हक? अमेरिकी राजदूत के बयान से मचा बवाल, अरब देशों का तीखा विरोध

तेल अवीव , एजेंसी। इस्राइल में अमेरिका के राजदूत माइक हुकाबी के एक बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। हुकाबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्राइल को मध्य पूर्व के बड़े हिस्से पर अधिकार हो सकता है। उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिकी रूढ़िवादी कमेंटेटर टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में की। कार्लसन ने बाइबिल के संदर्भ में पूछा था कि क्या इस्राइल को उस भूभाग पर अधिकार है, जो आज पूरे मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में फैला है। इस पर हुकाबी ने कहा अगर वे सब ले लें तो भी ठीक होगा। हालांकि बाद में उन्होंने जोड़ा कि इस्राइल फिलहाल अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं चाहता और उसे अपने वैध क्षेत्र में सुरक्षा का अधिकार है। अरब और मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया हुकाबी के बयान के बाद सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग ने कड़ी आपत्ति जताई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यधिक उग्र और अस्वीकार्य बयानबाजी बताया और अमेरिकी विदेश विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की। मिस्र ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन कहा और दोहराया कि इस्राइल का कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों या अन्य अरब भूमि पर कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। अरब लीग ने कहा कि ऐसे बयान क्षेत्र में धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं।

सीमाएं और संघर्ष का इतिहास : 1948 में स्थापना के बाद से इस्राइल की सीमाएं कई युद्धों, संघर्ष विराम समझौतों और शांति संधियों के चलते बदलती रही हैं। 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में इस्राइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, गाजा, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था। बाद में मिस्र के साथ शांति समझौते के तहत सिनाई खाली किया गया और 2005 में गाजा से एकतरफा वापसी की गई। हाल के महीनों में इस्राइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार और प्रशासनिक बदलावों के जरिए नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह वेस्ट बैंक के औपचारिक विलय की अनुमति नहीं देंगे।

चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट बने कुंग फू स्टार, एक साल में बदली तस्वीर; टेक रेस में अमेरिका को दी चुनौती

बीजिंग , एजेंसी। जो ह्यूमनॉइड रोबोट एक साल पहले सार्वजनिक प्रदर्शनों में गिरते-पड़ते नजर आते थे और जिनकी तकनीकी क्षमता पर संदेह जताया जाता था, वही अब कुंग फू फ्लिप्स, जिम्नास्टिक और हाई-प्रिसिजन डांस मूव्स के साथ चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में छा गए हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इस टीवी शो में चीनी स्टार्टअप्स के रोबोट्स ने यह साफ कर दिया कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रदर्शन ने जहां दर्शकों को रोमांचित किया, वहीं अमेरिका-चीन टेक रेस, नौकरियों के भविष्य और एआई आधारित मशीनों की बढ़ती ताकत पर वैश्विक बहस भी तेज कर दी है। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि असली परीक्षा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और जटिल मानवीय वातावरण में

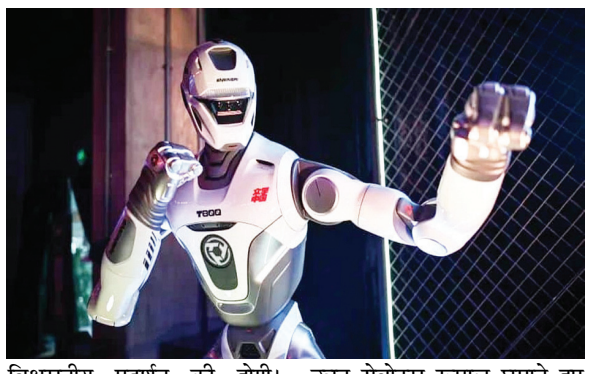

विश्वसनीय प्रदर्शन की होगी। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में इस बार कई स्टार्टअप कंपनियों के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। इन रोबोट्स ने कुंग फू स्टंट, समन्वित नृत्य और जिम्नास्टिक जैसे जटिल प्रदर्शन किए। यह प्रस्तुति 2025 के गाला से बिल्कुल अलग रही, जब अपेक्षाकृत कम उन्नत रोबोट्स रूमाल घुमाते हुए लोकनृत्य करते नजर आए थे और उनकी चाल अस्थिर दिखी थी। पिछले वर्ष अप्रैल में आयोजित एक रोबोट मैराथन भी सुर्खियों में रहा था, जहां कई रोबोट ठोकर खाते, गिरते या तकनीकी खराबी के कारण रुक जाते देखे गए थे। उस समय इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। लेकिन केवल एक वर्ष में तकनीकी सुधार ने धारणा बदल दी है। इस संबंध में सेमीएनालिसिस के विश्लेषक रेक नूटसेन ने कहा कि अब इन रोबोट्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके अनुसार स्प्रिंग गाला के प्रदर्शन के बाद रोबोट पहले से अधिक संतुलित, लचीले और सक्षम दिखे हैं। निर्माण और तैनाती में चीन की शुरुआती बढ़त बार्कलेज के आंकड़ों के अनुसार 2025 में दुनिया भर में लगभग 15,000 ह्यूमनॉइड रोबोट इंस्टॉलेशन हुए, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक चीन में थे, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत रही। बार्कलेज की थीमैटिक एफआईसीसी रिसर्च प्रमुख जोनिंत्सा तोदोरोवा के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी लगभग पूर्णतः वर्टिकली इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स वैल्यू चेन है।

बलूचिस्तान की अम्मा हूरी का इंतजार अधूरा, लापता बेटे की राह देखते-देखते दुनिया को कहा अलविदा

क्वेटा , एजेंसी। लूचिस्तान की एक साहसी मां, अम्मा हूरी, जो अपने लापता बेटे गुल मोहम्मद मर्री की वापसी के लिए पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रही थीं, का इंतजार कभी पूरा नहीं हुआ। 16 फरवरी को 80 वर्ष की उम्र में अम्मा हूरी ने अंतिम सांस ली। वह बलूचिस्तान की उन हज़ारों माताओं की प्रतीक बन गईं, जो पाकिस्तान सरकार की सामूहिक दंड की नीतियों का शिकार हो चुकी हैं।

अम्मा हूरी ने पिछले कई वर्षों में बिना थके अपने बेटे की वापसी के लिए शासन से कई बार अपील की, लेकिन उनका संघर्ष कभी सफल नहीं हुआ। वह जबरन गुमशुदगी के खिलाफ पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में धरनों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होती रही थीं। इसके अलावा, उन्होंने स्थानीय अदालतों और थानों में भी न्याय की मांग की, जिससे उनका संघर्ष एक प्रतीक बन गया था।

बलूचिस्तान में लापता लोगों की समस्या : रिपोर्टों के मुताबिक, अम्मा हूरी के बेटे गुल मोहम्मद मर्री को 2012 में कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जबरन गायब कर दिया गया था। इसके बाद अम्मा हूरी अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रही थीं, और यह संघर्ष पूरे बलूचिस्तान में एक राजनीतिक चेतना का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान की हर मां की तरह अम्मा हूरी ने भी लगातार प्रयास किए, लेकिन अंततः उनका इंतजार अधूरा ही रहा।

सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष : उनकी जैसी माताओं का दर्द अब बलूचिस्तान के जनजीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। ÷द बलूचिस्तान÷ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अम्मा हूरी जैसे संघर्षशील व्यक्तियों ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान राज्य के बीच के रिश्तों पर गहरा असर डाला है। बलूचिस्तान में लापता व्यक्तियों के परिवारों की अपीलों को पाकिस्तान सरकार द्वारा नजरअंदाज किया गया है, बावजूद इसके ये संघर्ष जारी रहे।

'अम्मा हूरी' का संघर्ष और उनकी विरासत : पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन के अनुसार, अम्मा हूरी ने जीवनभर अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में सार्वजनिक रूप से न्याय की मांग की। वह अक्सर सड़कों पर और लापता व्यक्तियों के कैंप में अपने बेटे के लिए न्याय की आवाज उठाती थीं। उनके संघर्ष की कहानी अब तक कई अन्य बलूच महिलाओं को प्रेरित करती है, जो आज भी लापता व्यक्तियों के लिए संघर्ष कर रही हैं।

नसरुल्लाह बलूच, जो वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के चेयरमैन हैं, कहते हैं, ÷अम्मा हूरी के निधन के बाद उनकी लड़ाई को कोई नहीं भुला सकता।÷ सोशल मीडिया पर उनके संघर्ष के वीडियो और संदेश आज भी वायरल हो रहे हैं, जो उनकी दृढ़ता और साहस का प्रतीक बने हुए हैं।

छह जनवरी के बाद ट्रंप के खाते बंद किए, जेपीमॉर्गन बैंक का कोर्ट में कबूलनामा; समझें पूरा विवाद

वॉशिंगटन , एजेंसी। जेपीमॉर्गन चेज ने अदालत में स्वीकार किया कि 6 जनवरी 2021 के हमले के बाद ट्रंप और उनकी कंपनियों के खाते बंद किए गए थे। ट्रंप ने बैंक और जेमी डाइमोन पर पांच अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने राजनीतिक भेदभाव और ब्लैकलिस्ट में डालने का आरोप लगाया है। छह जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के बैंक खातों को बंद किए जाने का मामला फिर चर्चा में है। जेपीमॉर्गन चेज ने पहली बार अदालत में स्वीकार किया है कि फरवरी 2021 में ट्रंप और उनकी कुछ कंपनियों के खाते बंद किए गए थे। यह स्वीकारोक्ति उस मुकदमे के दौरान सामने आई है जिसमें ट्रंप ने बैंक और उसके प्रमुख जेमी डाइमोन पर 5 अरब डॉलर का दावा ठोका है। ट्रंप का आरोप है कि उनके खाते राजनीतिक कारणों से बंद किए गए, जिससे उनके कारोबार को नुकसान हुआ। दायर हलफनामे में बैंक के पूर्व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डैन विल्कनिंग ने लिखा कि फरवरी 2021 में निजी बैंक और कमर्शियल बैंक से जुड़े कुछ खाते बंद करने की सूचना दी गई थी। अब तक बैंक केवल सामान्य तौर पर खाते बंद करने की नीतियों पर बात करता रहा था, लेकिन यह पहली बार है जब उसने सीधे तौर पर ट्रंप के खातों के बंद होने की पुष्टि की है। बैंक ने पहले कहा था कि यह मुकदमा बेबुनियाद है। ट्रंप ने यह मुकदमा पहले फ्लोरिडा की अदालत में दायर किया था, जहां अब उनका मुख्य निवास है। उनका कहना है कि बैंक ने 'ट्रेड लाइबल' किया और फ्लोरिडा के अनुचित और भ्रामक व्यापार कानून का उल्लंघन किया। मुकदमे में आरोप है कि जब खाते बंद किए जा रहे थे, तब ट्रंप ने जेमी डाइमोन से व्यक्तिगत रूप से बात की थी और उन्होंने मामले को देखने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रंप के वकीलों ने आरोप लगाया है कि बैंक ने राष्ट्रपति और उनकी कंपनियों को एक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। उनका कहना है कि इस सूची का उपयोग अन्य बैंक भी करते हैं। इससे भविष्य में नए खाते खोलने या सेवाएं लेने में दिक्कत आती है। वकीलों का दावा है कि इससे ट्रंप परिवार और उनके कारोबार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। यह मामला तथाकथित डीबैंकिंग की बहस को फिर से तेज कर रहा है। डीबैंकिंग तब होता है जब बैंक किसी ग्राहक के खाते बंद कर देता है या उसे सेवाएं देने से मना कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। कई रूढ़िवादी नेताओं का आरोप रहा है कि 6 जनवरी की घटना के बाद जोखिम के नाम पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जेपीमॉर्गन अब इस केस को न्यूयॉर्क स्थानांतरित कराने की कोशिश कर रहा है, जहां खाते संचालित होते थे। यह ट्रंप का किसी बड़े बैंक के खिलाफ पहला मामला नहीं है। मार्च 2025 में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने क्रेडिट कार्ड कंपनी कैपिटल वन पर भी इसी तरह का मुकदमा दायर किया था, जो अभी लंबित है।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान ने हालिया आतंकी हमलों के बाद अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी और अन्य आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इस्लामाबाद ने हमलों के पीछे अफगान धरती से संचालित नेटवर्क का दावा किया।

पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक यह इंटेलिजेंस आधारित, चयनित ऑपरेशन था, जिसमें प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और उसके सहयोगी गुटों के सात ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में मरने वाले लोगों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर बताया कि सीमा क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक गुट के ठिकानों पर भी प्रहार किया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले अफगानिस्तान के किस हिस्से में हुए। काबुल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अफगानिस्तान के पक्तिका में मदरसे पर हमला, कई जिलों में एयरस्ट्राइक : अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एक धार्मिक मदरसे पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा हवाई हमला किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई में लड़ाकू विमानों ने बरमल के अलावा नंगरहार प्रांत के खोगयानी जिले में भी कई ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक पक्तिका के बरमल और अर्गुन तथा नंगरहार के खोगयानी, बहसूद और गनी खेल जिलों में कई हवाई हमले किए गए हैं।

हालिया आत्मघाती हमलों के बाद कार्रवाई : यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकी

हमलों में तेजी आई है। बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर 11 सैनिकों और एक बच्चे की जान ले ली थी। इसके अलावा बन्नू जिले में भी एक और आत्मघाती हमले में दो सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्थान की परवाह किए बिना कार्रवाई करेगी। इस बयान से इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ते तनाव के संकेत मिले थे। अफगान धरती से साजिश का आरोप अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि हाल के हमले, जिनमें इस महीने इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हुआ आत्मघाती हमला भी शामिल है, अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व के इशारे पर अंजाम दिए गए। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगान क्षेत्र से संचालित हो रहा है, हालांकि काबुल और टीटीपी दोनों इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, पांच की मौत, 7 घायल

अमरावती (एजेंसी)। महाराष्ट्र के अमरावती जिले से सोमवार को धारणी तालुका के रानीगांव घाट मार्ग पर एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि सात गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दुर्घटना रानीगांव घाट सेक्शन में शिवाझिरी गांव पास हुई। जानकारी के मुताबिक पिकअप वैन संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़क से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक का नियंत्रण खो गया। संतुलन बिगड़ते ही वैन सड़क से फिसलकर सीधे गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा बेहद भीषण था। वाहन के खाई में गिरते ही उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। संकरी घाट सड़क और गहरी खाई के कारण बचाव अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की। कई घंटों की मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला। सभी सात घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल भवन में आधी रात पहुंची दिल्ली पुलिस... हंगामे का वीडियो वायरल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजधानी दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में रात को पुलिस की अचानक एंट्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों में हड़कंप मच गया था। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बिना कोई स्पष्ट वारंट दिखाए हिमाचल भवन के कमरों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मौजूद लोग विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे कि सरकारी जगह पर बिना आदेश कैसे प्रवेश हो सकता है। एक महिला, जो खुद को एडवोकेट बता रही है, कैमरे के सामने यह भी पूछती दिखती हैं कि 卐सर, आपने मेरे कमरे में घुसने के लिए अनुमति कैसे दी? महिला पुलिसकर्मी कहां हैं?卐 और एक व्यक्ति समय बताकर कहता है कि यह सवा 12 बजे के करीब हुआ था। विरोध के बाद पुलिस वापस लौटती दिख रही है। इस घटना ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत भी गरमाई है। धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया है कि हिमाचल सरकार दिल्ली किस उद्देश्य से गई थी, क्या यह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) की बहाली की मांग के लिए था या किसी और मायने में? उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ रिपोर्टों में यह भी चर्चा है कि दिल्ली पुलिस संभवतः एआई समिट के दौरान टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को खोजने के सिलसिले में हिमाचल भवन तक पहुंची थी, जहां पर कुछ प्रदर्शनकारी ठहरे हुए थे। लेकिन इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है।

छह महीने पहले ही जिसे किया डिपोर्ट वहीं बांग्लादेशी महिला फिर मुंबई में पकड़ाई

-पिछले दो सालों में 1237 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था

कश्मीर (एजेंसी)। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 46 साल की बांग्लादेशी नागरिक राबिया नासिर को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था, लेकिन हाल ही में वह विले पार्ले इलाके से फिर गिरफ्तार की गई है। उसे छह महीने पहले ही मीरा-भायंदर से गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया था। मुंबई के अलग-अलग इलाकों से पिछले महीने पकड़ी गई जुलेखा जमाल शेख और बिलकिस बेगम सिरमिया अख्तर ने भी पुलिस को बताया कि उन्हें अगस्त 2025 में बांग्लादेश भेजा गया था, लेकिन वे अवैध तरीके से फिर भारत लौट आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राबिया पिछले 25 सालों से मीरा-भायंदर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी, उसने पुलिस को बताया कि वह जंगलों के रास्ते सीमा पार कर वापस भारत में दाखिल हुई। आरोप है कि कुछ लोग सीमा सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत देकर दोबारा भारत में घुस रहे हैं। राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत पिछले दो सालों में 1237 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। मुंबई महानगर क्षेत्र के साथ-साथ पूरे राज्य में गिरफ्तारियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि मुंबई के सभी 93 पुलिस थानों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में एक हजार से ज्यादा अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया था। 2026 में भी सैकड़ों लोगों को पकड़ा है, जिन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। बता दें राबिया नासिर को 8 अगस्त 2025 को मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस ने डिपोर्ट किया था। हाल ही में उन्हें विले पार्ले (पश्चिम) से एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। इसके अलावा, पिछले सप्ताह वर्सोवा पुलिस ने अंधेरी (पश्चिम) से 21 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था, जिनमें 18 ट्रांसजेंडर शामिल थे। पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ एफआरओ को रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि जल्द से जल्द डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा सके।

पुलिसकर्मियों ने वायुसेना के जवान के साथ की मारपीट, कान का पर्दा फटा

कानपुर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना में तैनात एक जवान के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पिटाई के दौरान जवान के कान का पर्दा फट गया। वह पिछले तीन दिनों से एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित की मां ने डीसीपी साउथ कार्यालय में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

घाटमपुर थाना क्षेत्र के देवमनपुर गांव निवासी रेखा सचान के अनुसार, उनका बेटा नितीश सचान भारतीय वायुसेना में कार्यरत है। वह 19 फरवरी को नौरंगा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था। देर रात करीब साढ़े 11 बजे, जब वह मूसानगर रोड स्थित एक गेस्टहाउस से पैदल घर लौट रहा था, तभी पुलिस की गश्ती टीम ने उसे रोक लिया।

मैं कांग्रेस नेता की पत्नी को पाक एजेंट कहता हूं, अगर गलत लगे तो मुझ पर केस करें

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई पर किया बड़ा हमला

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर बड़ा हमला बोला उन्होंने कांग्रेस गोगोई पर पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। एक इंटरव्यू में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी लड़ाई गौरव गोगोई से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है। उन्होंने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए कहा कि ऐसे एजेंट भारत में नहीं चाहिए। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनके आरोप गलत हैं, तो गौरव गोगोई उन पर मुकदमा कर दें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में सरमा ने अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं गौरव गोगोई की पत्नी को पाक एजेंट कहता हूं। अगर किसी को यह गलत लगे तो वह मुझ पर केस कर सकता है। अगर मेरे पास कुछ गैरकानूनी है तो वह भी ले लो। वह कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वह खुद गलत हैं। अगर उन्होंने झूठा आरोप लगाया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सरमा ने जोर देकर कहा कि अगर वह कांग्रेस में बने रहते और 'जी-हुजूरी' करते, तो शायद सीएम बन जाते, लेकिन उनके लिए आत्मसम्मान और असम की जनता का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य की डेमोग्राफी को बदलने की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरमा ने कहा कि केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन सरकार' ने ही असम का उद्धार किया है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हुई और घुसपैठ पर लगाम लगी।

हिमंत सरमा ने कांग्रेस के शासन की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में कोई इंजन नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय विकास कार्य नहीं होते थे। कांग्रेस के समय तुलना के लिए कुछ नहीं था। मोदी सरकार के 11 साल में काम नजर आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उन्हें 'असामान्य' बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असामान्य हैं। चैट जीपीटी भी राहुल को असामान्य बता देगा। इतनी ठंड में हाफ टी-शर्ट कैसे पहन सकता है? ठंड में हाफ टी-शर्ट नॉर्मल व्यवहार नहीं है। साधु-संतों के कम कपड़े समझ में आते हैं, लेकिन राहुल असामान्य हरकतें करते हैं।

वहीं, घुसपैठियों के मुद्दे पर सीएम सरमा ने कहा कि घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना जरूरी है। घुसपैठियों ने असम की जमीन पर कब्जा किया है। असम समझौते के बाद घुसपैठिए बढ़ गए। वो फैसला करें कि जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। वह फैसला करें कि 11 बच्चे नहीं करेंगे। हिंदू के 3 बच्चे, घुसपैठियों के 11 बच्चे? असम की अस्मिता की रक्षा करनी होगी। मैं सेक्युलर लोगों से नहीं डरता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम की अस्मिता और जनता की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है, और वे किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। असम समझौते के बाद घुसपैठिये बढ़ गए. वो फैसला करें कि जमीन कब्जा नहीं करेंगे, वो फैसला करें कि 11 बच्चे नहीं करेंगे। हिंदू के 3 बच्चे, घुसपैठियों के 11 बच्चे? असम की अस्मिता की रक्षा करनी होगी. मैं सेक्युलर लोगों से नहीं डरता हूं।

रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक और तेजस, वायुसेना ने 30 विमानों की उड़ान पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में एक अग्रिम एयरबेस पर लैंडिंग के वक्त संदिग्ध ब्रेक फेल होने के कारण विमान रनवे से आगे निकल गया। इस घटना में विमान के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहा। यह घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है, जिस पर अभी तक वायुसेना की ओर से कोई औपचारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने एहतियाती कदम उठाते हुए लगभग 30 सिंगल-सीट तेजस जेट विमानों के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से उड़ान भरने से रोक दिया है। सूत्रों का कहना है कि विमानों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा पूरी होने तक यह बेड़ा जमीन पर ही रहेगा। तेजस विमान से जुड़ी यह तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और दूसरी घटना नवंबर 2025 में दुबई एयरशो के दौरान सामने आई थी। हादसों के बीच वायुसेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक विमानों को शामिल करने पर जोर दे रही है। वायु शक्ति अभ्यास से पूर्व एक प्रेस वार्ता में वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर ने कहा कि बल अपने बेड़े में नई पीढ़ी के और भी अधिक विमानों को शामिल करने का इच्छुक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की भूमिका की सराहना करते हुए उसे चर्चा का केंद्र बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायुसेना और अधिक बहु-भूमिका लड़ाकू विमानों को शामिल करने पर विचार कर रही है, चाहे वह राफेल हो या कोई अन्य विमान। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

2021 से जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर कमाए 4,405 करोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने सोमवार को कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत 2021 से जनवरी 2026 तक, उसने कबाड़ की बिक्री से कुल 4,405.28 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मुताबिक दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कबाड़ निपटान से 200.21 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जबकि जनवरी माह में स्वच्छता अभियान के तहत 5,188 कार्यालयों में 81,322 फाइलें छांटी गईं।

रिपोर्ट में विभाग के मुताबिक जनवरी में देशभर में 5,188 स्थानों पर सफाई अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए। करीब 4.34 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ है, जिसमें कोयला मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय का अहम योगदान रहा है। पिछले महीने, कबाड़ निपटान से 115.85 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई, जिसमें रेल मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और कोयला मंत्रालय जैसे मंत्रालयों का अहम योगदान रहा।

वहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावी अभिलेख प्रबंधन के तहत 1,82,000 फिजिकल फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 81,322 फाइलें अनावश्यक पाई गईं। 5,57,852 जन शिकायतों का निपटारा किया गया साथ ही 1,032 सांसद संबंधी संदर्भों और 375 राज्य सरकार संबंधी संदर्भों का भी निपटारा किया गया। इसमें आगे कहा गया है कि फाइलों की संख्या कम करने की पहल को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत लेनदेन स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2021 में 7.19 से घटकर जनवरी 2026 तक 4.31 हो गया है। जनवरी 2026 में बनाई गई कुल फाइलों में से करीब 93.81 फीसदी ई-फाइलें हैं। प्राप्त रसीदों में से करीब 95.29 फीसदी ई-रसीदें थीं और 65 मंत्रालयों और विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर कम से कम 90 फीसदी ई-फाइलों को अपनाया है। 26 जनवरी के लिए पंद्रह मंत्रालयों व विभागों की ई-रसीदों में 100 फीसदी हिस्सेदारी है।

राज्यसभा चुनाव में तेलंगाना से कांग्रेस को लग सकता है झटका... केसीआर एक सीट पर दावा करने की तैयारी में

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। वहीं तेलंगाना में भी 2 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन दो सीटों पर कांग्रेस की जीत अब तक तय मानी जा रही थी, लेकिन अब खेल बदलता नाराज आ रहा है। इस राज्य में भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस को चुनौती दे, लेकिन भारत राष्ट्र समिति के नेता के. चंद्रशेखर राव ने एक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया है। इन खबरों से कांग्रेस नेतृत्व को झटका लगाना लाजिमी है, जो पहले ही ज्यादातर राज्यों में सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। अप्रैल में दो सीटें खाली हो रही हैं। अब तक कांग्रेस तेलंगाना में मानकर चल रही थी कि इन दोनों सीटों पर आसानी से जीत मिल जाएगी।

लेकिन केसीआर ने जिस तरह से राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदलने की कोशिश की है, इससे कांग्रेस टेंशन में आ गई है। अब कांग्रेस के लिए स्पष्ट हो गया होगा कि मुकाबला गणित, गठबंधन और अन्य तमाम चीजों से तय होगा। मीडिया में खबरें हैं कि केसीआर किसी चर्चित व्यक्ति को उतारना चाहते हैं। विधानसभा रिकॉर्ड्स के अनुसार केसीआर के पास कुल 37 विधायक हैं। इसमें से 10 विधायक हैं, जो कांग्रेस के पास जा चुके हैं और उनकी अयोग्यता को लेकर मामला चल रहा है। इस मामले में 8 विधायकों पर बीआरएस की आपत्ति को स्पीकर ने खारिज किया है। वहीं दो पर अभी ट्राइब्यूनल में मामला लंबित है।

यदि एक राज्यसभा सीट जीतनी है, तब किसी भी दल को 41 विधायकों की जरूरत है। कुल 37 विधायकों का दावा करने वाली बीआरएस के साथ यदि उसके अपने सभी विधायक बने रहते हैं, तब बीआरएस को अलग से सिर्फ 4 विधायकों की ही जरूरत होगी। फिलहाल खबर है कि बीआरएस की ओर से उन दलों से वार्ता हो रही है, जिनके समर्थन से इस आंकड़े को हासिल कर सकते है। राज्य में कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। इसके अलावा सीपीआई के भी एक विधायक का कांग्रेस को समर्थन है। अब तक वह मान रही थी कि बीआरएस मुकाबले से दूर रहेगी। लेकिन जब एक राज्यसभा सीट हासिल करने की स्थिति केसीआर को दिखी, तब उन्होंने मुकाबले में उतरना ही ठीक समझा है।

फिलहाल पूरा मामला इस बात पर अटक गया है कि आखिर वे 10 विधायक किसके साथ जाते हैं, जो बीआरएस से बागी हुए हैं। इसके अलावा भाजपा और ओवीसी के एआईएमआईएम पर भी नजरें टिक गई हैं। राज्य में ओवैसी के पास कुल 7 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास भी 8 का समर्थन है। इस तरह से मुकाबला काफी पेंचीदा हो सकता है। साफ है कि एक सीट भले कांग्रेस आसानी से पा जाए, लेकिन दूसरी सीट जीतना टेढ़ी खीर बन सकता है। दरअसल कांग्रेस की आंतरिक कलह भी उसके लिए हालात मुश्किल कर रही है। दो सीटों में से एक पर अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से भेजा जा सकता है। अब रही बात दूसरी सीट की, तब उसके लिए सीएम के सलाहकार वी. नरेंद्र रेड्डी का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी भी मुकाबले में हैं।

बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में बगावत, भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को दिखाया आईना

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। इस बार विपक्ष के हमले से ज्यादा सत्ताधारी दल भाजपा के अपने ही विधायक विनय बिहारी के बयानों ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से विधायक विनय बिहारी ने राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह विफल बताते हुए इसे हटाने या सख्ती से लागू करने की मांग की है। उनके इस बयान ने न केवल एनडीए के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया है, बल्कि राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका भी दे दिया है।

बेतिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विनय बिहारी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में तंज कसते हुए कहा कि शराब मिलअता, तबे ना लोगवा हिलअता, जिसका अर्थ है कि शराब मिल रही है, तभी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। उन्होंने जमीनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि आज राज्य में शराब धड़ल्ले से बिक रही है और पीने वाले तथा बेचने वाले दोनों ही जेल जा रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं रुक रही। विधायक ने यहां तक कह दिया कि शादियों और बारातों में जाने पर अक्सर लोग नशे की हालत में मिल जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि या तो इस कानून को शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए या फिर इसे खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए ताकि राज्य को हो रहे आर्थिक नुकसान और जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोका जा सके।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में बड़े दावों के साथ बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। तब से अब तक लाखों लीटर शराब जब्त की गई है और लाखों लोग जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन समय-समय पर जहरीली शराब कांड में होने वाली मौतों ने इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। विनय बिहारी से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और रालोमो विधायक माधव आनंद भी इस कानून की समीक्षा की वकालत कर चुके हैं, लेकिन किसी एनडीए विधायक द्वारा इसे सीधे तौर पर हटाने की बात कहना पहली बार देखा गया है। इस बयान के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। जहाँ एक ओर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा और भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बचाव की मुद्रा अपनाते हुए कहा कि विधायक की बातों को गंभीरता से लेकर कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। राजद और कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार के भीतर ही इस कानून को लेकर एकराय नहीं है, जिसका सीधा फायदा माफिया और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को मिल रहा है। विपक्ष के अनुसार, पुलिस शराबबंदी को कमाई का जरिया बना चुकी है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है।

अजित पवार विमान हादसे की रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले आ जाएगी: मोहोल

-भतीजे रोहित पवार ने कई बार हादसे को लेकर साजिश का अंदेशा जताया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की मौत के मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके भतीजे रोहित पवार ने कई बार साजिश का अंदेशा जताया है। वहीं केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री और सांसद मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान हादसे की शुरूआती रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी। पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के निकट एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहोल ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट घटना के दिन से एक महीने के भीतर, 28 फरवरी को या उससे पहले जारी कर दी जाएगी।। इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई बार विमान कंपनी से जुड़ी कुछ अनियमितताओं और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों का दावा किया था। उन्होंने साजिश की भी आशंका जताई थी। शनिवार को कर्जत-जामखेड के विधायक ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए।

रोहित पवार ने पत्र में कहा कि वीएसआर कंपनी और राममोहन नायडू की पार्टी से इसके संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन संबंधों की जांच एक स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकार द्वारा की जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से। पत्र की एक कापी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। मोहोल ने कहा कि एजेंसी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि शुरुआती रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। जांच से जुड़ी हर जानकारी सबके सामने रखी गई है और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। मैं किसी की भी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहता। नागर विमानन मंत्रालय ने 19 फरवरी को कहा था कि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी।

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पिछले महीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की सीबीआई से जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विमान दुर्घटना के संबंध में सभी संदेह दूर हो जाएं

कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कोर्ट हुआ सख्त, चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए हंगामे पर दिल्ली की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के तरीके की तीखी आलोचना करते हुए इसे असहमति जताने का अनुचित तरीका करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया यह शर्टलेस विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीतिक छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने शनिवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों में बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना के नरसिंह यादव शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की हिरासत संबंधी अर्जी को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की कि आरोपी देश के विभिन्न दूर-दराज के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जिससे उनके फरार होने की आशंका प्रबल है। कोर्ट ने जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए बताया कि इस घटना के पीछे किसी बाहरी साजिश के संकेत मिल रहे हैं, जो मामले की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देते हैं।

अदालत के आदेश के अनुसार, इन आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने वैश्विक प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी वाले हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र भारत मंडपम में घुसने की एक सुनियोजित साजिश रची। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ऐसी टी-शर्ट पहन रखी थीं, जिन पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिखे थे। पुलिस रिकॉर्ड और मेडिको-लीगल मामलों (एमएलसी) के आधार पर यह भी सामने आया है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली गई और पुलिसकर्मियों पर शारीरिक हमले किए गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि लोकतंत्र में असहमति जताने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसा आचरण वैध विरोध की सीमाओं का उल्लंघन करता है। समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान इस तरह की हरकतें विदेशी हितधारकों के समक्ष देश की छवि को धूमिल करती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों के कई सहयोगी फिलहाल फरार हो सकते हैं, जो डिजिटल सबूतों और वित्तीय सुरागों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। गहन जांच की आवश्यकता पर बल देते हुए अदालत ने कहा कि ये अपराध अंतरराष्ट्रीय मंच पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121 (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना) और धारा 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब चारों आरोपियों को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रहकर पूछताछ का सामना करना होगा। इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक विरोध के गिरते स्तर पर भी एक नई बहस छेड़ दी है।